लखनऊ

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026

वर्ष : 11 | अंक: 326

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

जो हम दूसरों को देंगे, वही हमारे पास वापस आएगा—चाहे वह इज़्ज़त हो, सम्मान हो या धोखा।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi

NIGHT 28° Low

संक्षेप

सीजेपी के प्रदर्शन के चलते 16 मेट्रो स्टेशन सुरक्षा कारणों से बंद, इंटरचेंज चालू

नई दिल्ली। राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, आईटीओ और खान मार्केट समेत दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन अगले आदेश तक सुरक्षा कारणों से बृहस्पतिवार सुबह बंद कर दिए गए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने यह जानकारी दी। जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के जारी प्रदर्शन में भीड़ बढ़ने के बीच यह कदम उठाया गया है। हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए लाइन बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। डीएमआरसी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं।

अनंतनाग में पुलिसकर्मी की हत्या के बाद लश्कर के दो आतंकवादियों के घर ध्वस्त किए गए

श्रीनगर। कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक आतंकवादी हमले में पुलिसकर्मी की मौत के कुछ घंटे बाद प्रशासन ने लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादियों के मकान ढहा दिए। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सक्रिय आतंकवादी आदिल ढोकर और हारून रशीद गनई के मकान बुधवार और बृहस्पतिवार की दरम्यानी रात ध्वस्त कर दिए गए। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई बुधवार दोपहर अनंतनाग के लाल चौक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन की एक आतंकवादी द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के कुछ ही घंटे बाद की गई। कश्मीर में इससे पहले भी सक्रिय आतंकवादियों के मकान ढहाए गए हैं, लेकिन हिंसा की घटनाओं में कमी आने के कारण पिछले लगभग एक वर्ष से ऐसी कार्रवाई बंद थी।

विमान भी अपना, एयरपोर्ट भी अपना और अब एयरलाइन भी अपनी! अडानी अब इंडिगो-एयर इंडिया को देंगे टक्कर

नई दिल्ली, एजेंसी। अडानी ग्रुप ने सरकार से एक नियम में बदलाव की मांग की है। यह नियम अभी दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेटर्स को किसी शेड्यूल्ड एयरलाइन में 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी रखने से रोकता है। अगर इस बदलाव को मंज़ूरी मिल जाती है, तो इससे ग्रुप के लिए अपनी एयरलाइन शुरू करने और भारत के एविएशन मार्केट में इंडिगो और एयर इंडिया के दबदबे को चुनौती देने का रास्ता खुल सकता है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब ऐसी रिपोर्टें हैं कि सरकार अडानी ग्रुप और GMR एयरपोर्ट्स जैसे एयरपोर्ट ऑपरेटरों को एयरलाइन बिज़नेस में आने की इजाज़त देने पर विचार कर रही है। इसका मकसद उस मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ाना है जहाँ इंडिगो और एयर इंडिया मिलकर घरेलू पैसेंजर ट्रैफिक का लगभग 90% हिस्सा संभालते हैं।

>> पीएम मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे पर दिया बयान >> नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तीखा पलटवार

फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन होगा: पीएम मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के जंतर मंतर पर गुरुवार को भी प्रदर्शन जारी है। इससे पहले बुधवार को प्रदर्शन के दौरान हिंसा की खबरें भी सामने आई जिसमें कई पुलिसवाले घायल हुए हैं। दूसरी ओर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सुबह-सुबह पेपर लीक के मुद्दे पर बयान जारी किया है। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट कर के पेपर लीक के मामले में स्टूडेंट्स को डायरेक्ट मैसेज दिया है और बताया है कि सरकार इस मामले में कितनी संवेदनशील है। पीएम मोदी ने कहा है कि पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। उन्होंने कहा है कि देश के युवाओं का भविष्य हमारी प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा- 'देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।'

अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर दी प्रतिक्रिया

अमित शाह ने पीएम मोदी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'युवाओं का हित और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी का यह महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा।'

सोनम ने दिया अनशन खत्म करने का संकेत

दूसरी ओर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन खत्म करने के संकेत दे दिए हैं। बता दें कि मंगलवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी। जानकारी के अनुसार, सरकार ने सोनम वांगचुक को भरोसा दिलाया है कि एजुकेशन सिस्टम में जरूरी बदलाव लाने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं, सोनम ने अस्पताल से वीडियो जारी कर के कहा है कि सरकार अगर छात्रों पर बल प्रयोग रोकने और मुकदमे वापस लेने का भरोसा दे तो वह अनशन खत्म कर सकते हैं।

संसद में भी चर्चा कराने की तैयारी

दूसरी ओर सरकार ने संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा कराने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संसद में पेपर लीक पर चर्चा का भरोसा दिया है। उन्होंने विपक्ष को दिन और समय तय करने का हक दिया है।

'आपने युवाओं के भविष्य को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया'

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को नीट पेपर लीक विवाद को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को तबाह करने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता की यह तीखी प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस हालिया बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने पेपर लीक के दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाने के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि युवाओं का कल्याण और भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। X पर एक पोस्ट में, कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था पर 'कब्ज़ा कर लिया गया है और उसे बर्बाद कर दिया गया है' और सरकार पर इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को बचाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, 'आप ही हैं जिन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। आपने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह कब्ज़ा करने और उसे बर्बाद करने की इजाज़त दी और उसे बढ़ावा दिया – और इसके लिए ज़िम्मेदार हर व्यक्ति को बचाया।' छात्रों की मांगों को दोहराते हुए, राहुल गांधी ने ये मांगें रखीं:

धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें। छात्रों से माफ़ी मांगें। उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जिन्होंने उनके साथ मारपीट की।

पेपर लीक पर एक्शन में केंद्र सरकार! देश के 4 शहरों में बनावाएगी फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसमें रोजाना होगी सुनवाई

नई दिल्ली, एजेंसी। पेपर लीक मामले को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार एक्शन में दिख रही है। दरअसल, पेपर लीक के मामले में औरंगाबाद और महाराष्ट्र के नागपुर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता और मध्य प्रदेश के जबलपुर में दर्ज हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार इन चारों जगहों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए इन राज्यों के चीफ जस्टिस को पत्र लिखेगी। इन फार्स्ट ट्रैक कोर्ट में रोज सुनवाई करवाई जाएगी जिससे दोषियों को जल्दी सजा मिले। इससे पहले आज (गुरुवार को) सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कही थी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया था, 'देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।' अपने X पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा, 'विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।'

नीट पेपर लीक पर जंतर-मंतर से संसद तक प्रदर्शन

गौरतलब है कि नीट पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर से संसद तक प्रोटेस्ट जारी है। संसद में आज चौथे दिन भी हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से आज भी दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पेपर लीक को लेकर कांग्रेस लगातार सदन में चर्चा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है।

विपक्ष लगातार बदल रहा अपना गोल पोस्ट- सरकार

वहीं, सरकार का कहना है कि विपक्ष लगातार अपना गोल पोस्ट बदल रहा है। सरकार की ओर से संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार और NDA चाहती है कि पेपर लीक के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हो लेकिन ये चर्चा बिना शर्त हो, जबकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उसके बाद ही संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी विपक्ष को घेरा था और कहा था कि पेपर लीक पर सरकार संसद में चर्चा को तैयार है लेकिन राहुल गांधी बताएं वो सेलेक्टिव क्यों हैं।

सरकार चर्चा चाहती तो पहले दिन ही कर लेती: खरगे

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के आरोप का खंडन किया कि विपक्ष परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक पर चर्चा से भाग रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार असल में बहस चाहती, तो उसने विपक्ष की पहली मांग पर ही इसकी अनुमति दे दी होती। पत्रकारों से बात करते हुए, खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस मुद्दे पर उनके इरादों पर सवाल उठाया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। खरगे ने कहा 'अगर वे चर्चा के लिए तैयार होते, तो जिस दिन हमने इसकी मांग की थी, उसी दिन से शुरू हो जाती। वे तैयार क्यों नहीं थे? बाद में, आपने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। हम सांसद हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के लोगों ने खुद आज दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। जब तक वे (धर्मेंद्र प्रधान) इस्तीफा नहीं देते, तब तक यह काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री अब तक चुप क्यों थे? अगर इस स्थिति के लिए कोई जिम्मेदार है, तो वह प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने खुलेआम अपने सांसदों को छात्रों के आंदोलन का विरोध करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री की मंशा सही नहीं है। उन्होंने कभी भी अहम मुद्दों पर बात नहीं की है। उन्होंने आगे कहा, 'हम नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहते थे। लेकिन सरकार इसके लिए सहमत नहीं हुई। उन्होंने राहुल , प्रियंका और अन्य लोगों का अपमान किया। हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही किसी भी चर्चा के लिए तैयार होंगे।'

प्रियांक खरगे ने सरकार से क्या सवाल पूछा?

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने शिक्षा मंत्री को बदलने से इनकार करने के केंद्र के फैसले की आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार लाखों छात्रों के भविष्य की बजाय एक मंत्री को प्राथमिकता क्यों दे रही है। प्रियांक खरगे ने कहा, 'अगर सरकार अब भी छात्रों की भावनाओं को नहीं समझती है, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्मेंद्र प्रधान भारत सरकार के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? वे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मंत्रिमंडल के लिए कौन से रहस्य छिपा रहे हैं?

मुख्यमंत्री योगी का कांग्रेस-SP पर बड़ा आरोप, छात्रों को कर रहे बदनाम

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे NEET विरोध-प्रदर्शनों के बीच दिल्ली में संसद सत्र को घेरकर अशांति फैलाने और छात्रों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गोरखपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया और विस्थापित किया गया, तो विपक्षी दल चुप रहे; लेकिन जब नरेंद्र मोदी सरकार ने हिंदुओं की सुरक्षा और बचाव पर ज़ोर दिया, तो उन्होंने एक नकारात्मक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने देखा होगा कि कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में संसद सत्र के दौरान हंगामा किया, माहौल खराब किया और अशांति फैलाकर छात्रों को बदनाम करने की कोशिश की। कांग्रेस सरकार के समय, जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया और उन्हें विस्थापित किया गया, तब वे चुप रहे। लेकिन जब मोदी सरकार ने हिंदुओं की सुरक्षा और बचाव की बात की, तो इन लोगों ने इसके खिलाफ़ नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की। उन्होंने विरोध-प्रदर्शन, आंदोलन, तोड़-फोड़, आगजनी और ऐसी ही दूसरी गतिविधियां करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने आगे दावा किया कि न केवल दिल्ली में, बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में भी हालात बिगाड़ने की कोशिशें की गईं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने न सिर्फ़ दिल्ली में, बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे राज्यों में भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की।

धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा दें : अरविंद केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों की चिंताएं दूर नहीं होतीं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। X पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने लिखा कि आज सुबह प्रधानमंत्री ने घोषणा की – पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का क्या हुआ? मोदी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री का बयान किसी ऐसे व्यक्ति जैसा लगता है जो हार चुका हो, दिशाहीन हो, लेकिन अहंकारी भी हो। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की घोषणा की आलोचना करते हुए कहा कि यह छात्रों की मांग के मुकाबले नाकाफी है और केंद्र सरकार पर उन्हें गुमराह करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत में रेप और POCSO जैसे मामलों के लिए पहले से ही फास्ट-ट्रैक कोर्ट हैं, लेकिन इनमें से कई कोर्ट या तो सुनवाई नहीं कर पाते या फिर सामान्य कोर्ट से ज़्यादा समय लेते हैं।

सरकार-प्रदर्शनकारी मिलकर निकालें समाधान : मायावती

बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती ने गुरुवार को केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वे NEET पेपर लीक में गड़बड़ियों को लेकर जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन का शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करें। X पर एक पोस्ट में मायावती ने कहा कि संसद के पास चल रहे अनिश्चितकालीन विरोध-प्रदर्शन ने छात्रों और उनके परिवारों पर पेपर लीक और दूसरी अनियमितताओं के गंभीर असर को उजागर किया है। मायावती ने लिखा कि राष्ट्रीय राजधानी में संसद के पास जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेतृत्व में कई दिनों से अनिश्चितकालीन विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। यह प्रदर्शन NEET जैसी बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक और दूसरी अनियमितताओं के कारण छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ने वाले गंभीर असर को उजागर कर रहा है। मायावती ने कहा कि इस विरोध-प्रदर्शन ने सड़कों से लेकर संसद तक भारी हंगामा खड़ा कर दिया है और बाद में इसके राजनीतिकरण ने इसे सरकार के साथ सीधे टकराव में बदल दिया है।

गलतियां नहीं मान रही सरकार: ओवैसी

AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को युवाओं का अपमान करने और अपनी गलतियों को न मानने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। ANI से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि सरकार युवाओं को नज़रअंदाज़ करती है और उनसे बातचीत करने से बचती है। उन्होंने कहा कि आप छोटे बच्चों को बुलाते हैं और उन्हें दो घंटे तक घर पर बिठाए रखते हैं। आप उनसे बात नहीं करते, बल्कि उन्हें अपमानित करते हैं। आपको उनसे बात करना सीखना चाहिए। यह सब आपकी, यानी सरकार की वजह से हो रहा है। ओवैसी ने अलग-अलग संकटों के लिए विपक्ष को ज़िम्मेदार ठहराने पर सरकार की आलोचना की और उनसे आरोप-प्रत्यारोप का खेल बंद करके अपनी गलतियाँ मानने को कहा। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है, उसके लिए आप विपक्ष को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? आपसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, उन्हें आपको मानना चाहिए। आप तो उन्हें मान भी नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पास भारी बहुमत है और आप हम सबको दबा देंगे। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप इसे कम आंक रहे हैं।

BJP के गुंडे कर रहे पत्थरबाजी, CJP को बदनाम करने की साजिश

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि अभिजीत दिपके ने गुरुवार को आरोप लगाया कि छात्रों के चल रहे विरोध-प्रदर्शन को जानबूझकर बाधित करने के लिए बाहर से लोगों को भेजा जा रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंकने और प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए दिपके ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन एक महीने से बिना किसी ऐसी घटना के चल रहा था, लेकिन प्रदर्शन के जोर पकड़ने के बाद स्थिति बदल गई।

जो लोग आस्था, नौजवानों और किसानों से खिलवाड़ करते थे उनके उपदेश हास्यास्पद लगते हैं: सीएम योगी

आर्यावर्त क्रांति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर में 995 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 14 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। जनपद में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने समाजवाद पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि सपा के लोग युवाओं के साथ छल करने का काम करते थे। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे और अराजकता चरम पर थी।

सीएम योगी ने कहा- 'साल 2007 से लेकर 2017 तक 10 वर्ष में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने प्रदेश की 29 चीनी मिलों को बंद किया था। ओने-पौने दाम पर चीनी मिलों को बेच दिया गया। इन नौजवानों को बेरोजगार करने का पाप किया। पहले नौकरी निकलती थी। तो युवाओं के साथ समाजवादी पार्टी के लोग छल करते थे, भेदभाव करते थे। सिपाही सिंडिकेट का कब्जा होता था नौकरी पर। नौकरी पर नौजवान को नहीं आने देते थे। आज तो मैं कह सकता हूं, नौकरी आती है बिना भेदभाव के चयन होता है।₹ ये भेदभाव नौजवानों के साथ किसी ने किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। उनकी नौकरियों में डकैती डाली गई। उनके अधिकारों को कम करने का काम किया गया। उसे हर प्रकार से ठगने का काम किया गया।

गोरखपुर के नौजवानों की बात

सीएम योगी ने कहा- 'अब गोरखपुर का नौजवान भी यूपी पुलिस की भर्ती होती हो या शिक्षकों की भर्ती होती हो या यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में उप जिलाधिकारी या डिप्टी एसपी के पद पर उनका चयन होता है और लखनऊ में जब मैं उससे पूछता हूं कि भई कहां से, कहता है मैं गोरखपुर से हूं। जोर से बोलता है मैं गोरखपुर से हूं तो मुझे अच्छा लगता है। गोरखपुर के नौजवान का सिलेक्शन बिना किसी सिफारिश के उसकी योग्यता के अनुसार हो जाता है।'

'जिन्होंने आस्था पर प्रहार किया, आज ठेकेदार बने'

सीएम योगी ने कहा- '2017 के पहले तो दंगे होते थे। अराजकता चरम पर थी। होली के अवसर पे दंगा, विजया दशमी और दुर्गा पूजा के समय दंगा, रामनवमी के रामनवमी के समय दंगा, जन्माष्टमी के आयोजन को नहीं होने देते थे, कांवड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे। यानी जो आस्था पर उस समय प्रहार करते थे आज वे सबसे बड़े आस्थावान बनने का ठेका ले चुके हैं। सबसे बड़े आस्थावान बन रहे हैं। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधाएं खड़ी कीं, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राम भक्तों पर गोलियां चलाईं, राम मंदिर के मार्ग के लिए बाधा खड़ी करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े किए विरोध में। वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं।' आपको बता दें कि बुधवार को भी गोरखपुर में सीएम योगी ने एक सभा की थी और चुनावी बूथ की अहमियत पर बात की थी।

बढ़ने वाली है वायुसेना की ताकत, जल्द मिलेगा 'आसमान का प्रहरी'

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के स्वदेशी रक्षा बेड़े को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महत्वाकांक्षी AEW&C Mk-II (एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल) प्रोग्राम को अब और तेज रफ्तार मिल गई है। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए DRDO ने दो बड़ी कंपनियों के साथ अहम समझौते किए हैं। इन समझौतों पर 22 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में रक्षा सचिव और DRDO के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए।

* AIESL: DRDO के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स (CABS) ने AIESL के साथ करार किया है। इसके तहत 6 एयरबस A321 (Airbus A321) विमानों को सामान्य कमर्शियल उड़ानों वाले रूप से बदलकर विशेष सैन्य प्लेटफॉर्म (Military Configuration) में तैयार किया जाएगा। इन्हीं विमानों पर बाद में AEW&C Mk-II का शक्तिशाली रडार और सिस्टम लगाया जाएगा।

अडानी डिफेंस (ADSTL): अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को इस प्रोजेक्ट के लिए डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर (DcPP) बनाया गया है। कंपनी इस पूरे मिशन सिस्टम के विकास और निर्माण में DRDO का पूरा सहयोग करेगी।

दिन में पूछा मुआवजा कैसे मिलेगा? शाम को कर दी मां की हत्या, बेटे ने किया कत्ल, जानवर पर लगा दिया इल्जाम

जिले में ऐसी कई घटनाएं सामने आ रहीं हैं, जिनमें हत्या को गुलदार का हमला बताया गया। मामलों की जांच में सही स्थिति का खुलासा हो गया। ऐसे संदिग्ध मामलों को और बारीकी से देखा जाएगा ताकि सही स्थिति का पता चल सके।

- जय सिंह कुशवाह, डीएफओ

आर्यावर्त संवाददाता

बिजनौर। यूपी के बिजनौर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां हीमपुर दीपा थाना इलाके के गांव अजुपुरा जट में सोमवार की शाम बीरो देवी (65) की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। महिला की मौत गुलदार के हमले में नहीं हुई थी बल्कि पांच लाख रुपये मुआवजे के लालच में बेटे बहाल सिंह उर्फ मनिया ने ही गला दबाकर उसकी हत्या की थी।

पुलिस ने बुधवार को हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। खास बात यह भी है कि आरोपी ने उस दिन दोपहर में ही डीएफओ ऑफिस जाकर गुलदार के हमले में मुआवजा मांगा था। जब पता चला कि मौत पर पांच लाख का मुआवजा मिलने का प्रावधान है तो शाम को उसने मां की हत्या कर दी और गुलदार के हमले का शोर मचा दिया। यह बात पुलिस जांच में सामने आई है।

बीरो देवी सोमवार की शाम छोटे बेटे बहाल सिंह उर्फ मनिया के साथ चारा लेने गई थी। बहाल सिंह ने गुलदार के हमले में अपनी मां के मरने की सूचना डायल -112 पुलिस और ग्रामीणों को दे दी थी। उसने पुलिस और गांव वालों को मां को बचाने के लिए गुलदार से लड़ने की झूठी कहानी भी सुना दी। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव नहीं उठाने दिया था।

करीब दो घंटे बाद तहसीलदार एवं वन विभाग चांदपुर के रेंजर दुष्यंत मावी ने मृतका के आश्रितों को पांच लाख रुपये की मुआवजा दिलाने का लिखित आश्वासन देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पता लगा कि वृद्धा की मौत गुलदार के हमले में नहीं बल्कि गला दबाने से हुई थी। पुलिस ने बीरो देवी के बेटे बहाल सिंह को मंगलवार की देर शाम हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि उसने पुलिस और ग्रामीणों के समक्ष घटना में स्वयं शामिल होना स्वीकार किया। बहाल सिंह ने बताया कि काफी समय से उसकी मां से किसी न किसी बात को लेकर अनबन रहती थी। सोमवार को भी जंगल में किसी बात पर मां ने उसे गाली दे दी।

आवेश में आकर उसने अपने गन्ने के खेत में कुछ दूर अंदर ले जाकर मां का गला दबाकर हत्या कर दी। राज छिपाने तथा मुआवजे के पांच लाख रुपये के चक्कर में मां की मौत गुलदार के हमले से होना बताया। सीओ चांदपुर देश दीपक ने बताया कि पुलिस ने बुधवार को बीरो देवी के बड़े बेटे रूपचंद की ओर से दी गई तहरीर पर कार्रवाई करते हुए छोटे बेटे बहाल सिंह उर्फ मनिया का चालान कर दिया।

घटना के खुलासे से ग्रामीण हतप्रभ

बीरो देवी की हत्या के खुलासे से ग्रामीण हैरत में हैं। साथ ही तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि बेटे ने ही मां को मौत की नींद सुला दिया। उसने खून के रिश्तों का ही कत्ल नहीं बल्कि मां और बेटे के विश्वास और पवित्र रिश्ते को भी कलंकित किया है।

पत्नी बोली, सब कुछ ठीक था

बहाल सिंह उर्फ मनिया की पत्नी डोली को अपने पति द्वारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने पर विश्वास नहीं है। थाने में उसने रो-रोकर बताया कि उनकी गृहस्थी ठीक चल रही थी। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, उसे विश्वास नहीं हो रहा है। अब वह अपने दो छोटे बच्चों का पालन कैसे करेगी?

पहले खुद के लिए मांगा था मुआवजा

सोमवार दोपहर बहाल सिंह बिजनौर डीएफओ ऑफिस आया था। खुद पर खरोंच के निशान दिखाकर गुलदार का हमला होने की बात बताई और मुआवजा मांगा। डीएफओ जय सिंह कुशवाह ने बताया कि उसे बताया गया था खरोंच में मुआवजा नहीं मिलता। यदि घायल हुए हैं तो चिकित्सक से मेडिकल बनवाना होगा। उसने मुआवजे के नियम भी पूछे थे। इसके बाद वह चला गया था। शाम को उसकी मां की मौत गुलदार के हमले में होने की सूचना आई थी।

इंसान ने निगली जिंदगी, इल्जाम जानवर पर लगाया

बिजनौर जिले में गुलदार के खौफ के बीच इंसान की खतरनाक फितरत भी सामने आने लगी है। लालच और विवाद में लोग हत्या इल्जाम गुलदार पर लगा रहे हैं। हाल ही में अजुपुरा जट में भी ऐसा ही हुआ। बेटे ने मां की हत्या का ठींकरा गुलदार के सिर पर मढ़ने की कोशिश की लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो गया।

बीते एक वर्ष में हत्या के ऐसे दो मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही महिलाओं के लापता होने पर उन्हें गुलदार के द्वारा उठा ले जाने का भी शोर मचाया गया। बाद में कहानी कुछ और ही निकलकर सामने आई।

15 नवंबर 2025 को नांगल सोती क्षेत्र के ग्राम तिसोतरा निवासी सौरभ तोमर की मौत के लिए भी गुलदार के हमले को जिम्मेदार ठहराया गया था। बाद में पुलिस जांच में सामने आया कि उसकी हत्या पिता सुभाष तोमर ने की थी। गले पर धारदार हथियार के निशान को गुलदार के हमले का निशान बताते हुए पिता ने अपना अपराध छिपाने की कोशिश की थी। बीते सोमवार को अजुपुरा जट में बहाल सिंह उर्फ मनिया पर मां बीरो देवी की हत्या का आरोप है। पुलिस ने पांच लाख रुपये के लालच में की हत्या करने की बात बताई है जबकि आरोपी ने वृद्धा की मौत गुलदार के हमले में होना बताया था।

11 नवंबर 2025 को किरतपुर के एक गांव में एक महिला कूड़ा डालने के लिए सुबह छह बजे घर से निकली थी। घर नहीं पहुंचने पर गांव में गुलदार के उठा ले जाने का शोर मच गया। पूरा प्रशासनिक अमला दौड़ा। महिला भी अपना सामान इस तरह से फेंक कर निकली थी, जिससे गुलदार के उठाकर ले जाने की पुष्टि हो सके।

हालांकि पुलिस ने महिला को देहरादून से ढूंढ निकाला था। 23 अक्तूबर 2025 को नहटौर के गांव नन्हेड़ा की रहने वाली एक युवती के खेत से लापता होने के बाद परिवार वालों ने शोर मचाया कि गुलदार उठाकर ले गया। सुबह से लेकर शाम तक पुलिस और वन विभाग युवती को ढूंढता रहा। बाद में पुलिस ने इस युवती को भी देहरादून से ढूंढ निकाला था।

चिकित्सक के अभाव से जूझ रही है पीएचसी

कुड़वार/सुल्तानपुर। जनता के इलाज का जिम्मा उठाने वाली तीन पीएचसी चिकित्सक की कमी से जूझ रही है। चिकित्सक के स्थानांतरण के बाद अभी तक विभाग द्वारा इन पर तैनाती नहीं की गई। बता दे स्थानीय सीएचसी के अंतर्गत तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अझुई, भंडरा, हरखीपुर व अलीगंज संचालित है। एक पीएचसी पर लगभग 50 हजार लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल का जिम्मा है। जहां से आम जन अपनी बीमारियों का इलाज कराते है। लेकिन भंडरा, अझुई व हरखीपुर पीएचसी पर चिकित्सक की तैनाती नहीं है। अलीगंज पर डॉ अनिमेष व डॉ अतुल मरीजों को सेवा दे रहे है। जबकि पीएचसी हरखीपुर फार्मासिस्ट दिनेश सिंह, अझुई फार्मासिस्ट ज्योति भूषण त्रिपाठी व भंडरा फार्मासिस्ट दीपक त्रिपाठी के सहारे चल रही है। चिकित्सकों के स्थानांतरण के बाद इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विभाग द्वारा चिकित्सक की तैनाती नहीं की गई।

'मुस्कान और दामिनी की तरह मेरी पत्नी प्रेमी संग मिलकर मारने की दे रही धमकी' डरे पति ने पुलिस से मांगी जान की भीख

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले युवक ने पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या की सजिश रचने का आरोप लगाया है। युवक ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी उसे मुस्कान रस्तोगी, दामिनी पंवार, रविता और कोमल की तरह वारदात करने की धमकी दे रही है। युवक ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर सकती है। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्ष को जांच के लिए बुलाया है।

सिविल लाइन थाने की कॉलोनी निवासी युवक थाने पहुंचा। युवक ने थाना प्रभारी सौरभ शुक्ला से बताया कि उसकी शादी 22 जून 2025 को मेरठ की ही निवासी युवती से हुई थी। आरोप लगाया कि शादी के बाद पता चला कि महिला का किसी अन्य युवक से प्रेम प्रसंग है।

पत्नी कई बार विवाद करके घर चली जाती थी। शक होने पर छानबीन की तो पत्नी के प्रेम प्रसंग का खुलासा हुआ। विरोध करने पर पत्नी ने अपने प्रेमी से हत्या कराने की धमकी दिलाई। युवक ने बताया कि 14 जुलाई 2026 को रात करीब 10 बजे मेडिकल किसी काम से जा रहा था। रास्ते में पत्नी को उसके प्रेमी के साथ देखकर बाइक रुकवा ली। मौके पर पत्नी ने हंगामा कर दिया। उसने घटना के समय की वीडियो भी बनाई है। उसका कहना है कि मुस्कान (मेरठ के ब्लू ड्रम केस की आरोपित), रविता, कोमल और दामिनी की तरह पत्नी उसकी हत्या करा सकती है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि शिकायत पर दोनों पक्षों को परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया है।

डायरिया नियंत्रण व रोकथाम की अनूठी पहल

जागरूकता की अलख जगायेंगे प्रचार वाहन

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। शून्य से पांच साल तक के बच्चों को डायरिया से सुरक्षित बनाने के लिए जनपद में एक अनूठी पहल की गयी है। इसके तहत डायरिया के प्रति जागरूकता सम्बन्धी संदेशों वाले पोस्टर-बैनर से सुसज्जित प्रचार वाहनों को गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विकास सिंह और डॉ. आर. के. शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार वाहन गली-मोहल्लों में पहुंचकर जन-जन तक डायरिया से डरने नहीं बल्कि सतर्क रहने का सन्देश पहुंचाएंगे। इस मौके पर डॉ. विकास सिंह ने कहा कि शून्य से पांच साल तक के बच्चों को डायरिया से सुरक्षित बनाने के लिए जन जागरूकता बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह प्रचार वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर शून्य से पांच साल तक के बच्चों में डायरिया के लक्षण, कारण और बचाव आदि के बारे में प्रचार-प्रसार करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में 25 अगस्त तक डायरिया रोको अभियान चलाया जा रहा है। डायरिया रोको अभियान में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू भी "डायरिया से डर नहीं" कार्यक्रम के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। अभियान की इस साल की थीम-"स्वच्छ जल, समुचित उपचार- डायरिया से बचें हर बार" तय की गयी है। अभियान का उद्देश्य बच्चों में डायरिया की रोकथाम, ओआरएस व जिंक के उपयोग को प्रोत्साहन देना और समुदाय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक रघुबीर सिंह ने कहा कि बच्चे को दिन भर में तीन या तीन से अधिक बार पतली दस्त हो तो समझना चाहिए कि बच्चा डायरिया से ग्रसित है और ऐसे में उसको तत्काल ओआरएस का घोल देना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न होने पाए, साथ ही निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करना चाहिए। इस मौके पर जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक चंद्रशेखर, राजकुमार एवं पीएसआई इंडिया से मोहम्मद रिजवान एवं ममता सैनी आदि मौजूद रहे।

मृतक छात्रा के माता पिता को सौंपा गया एक लाख सहयोग राशि का चेक

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। विगत 14 जुलाई को कंपोजिट विद्यालय पखरौली वि.क्षे. भदैया में पढ़ने वाली कक्षा एक की छात्रा अश्विनी प्रजापति की विद्यालय के गेट सामने ऑटो रिक्शा से हुई दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई थी। उक्त दुर्घटना के बाद बी.आर.सी. भदैया पर बी.ई.ओ. भदैया शिव शंकर मिश्र एवं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष दिनेश उपाध्याय के नेतृत्व में शोक सभा का आयोजन करके ब्लॉक में कार्यरत शिक्षकों से मृतक बच्ची के परिवार को सहायता राशि देने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में आज ब्लॉक संसाधन केंद्र भदैया पर शिक्षकों द्वारा एकत्रित एक लाख रुपये का चेक बच्ची के माता पिता को बी ई ओ शिवशंकर मिश्रा जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ दिनेश उपाध्याय एवं जिलामंत्री जूनियर शिक्षक संघ कलहू पाल के द्वारा प्रदान किया गया। उक्त अवसर पर ब्लॉक मंत्री बिपिन यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र राय कार्यालय सहायक श्याम किशोर दूबे, जबीउल्ला, विष्णु शंकर, सतीश, संजय कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। खण्ड शिक्षा अधिकारी शिव शंकर मिश्र ने इस नेक काम को करने हेतु ब्लॉक के सभी शिक्षकों, संकुल प्रभारियों एवं संगठन के पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया ।

छात्र आंदोलन में शामिल होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर को नौकरी से निकाला, कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बरेली। बरेली में गन्ना उत्पादक (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय बहेड़ी के असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉमर्स) डॉ. मोहित भारद्वाज ने जिलाधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर आरोप लगाया है कि उन्हें बिना कारण बताए, बिना नोटिस, बिना विभागीय जांच और बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के सेवा से हटा दिया गया। आरोप है कि जंतर मंतर पर धरना में शामिल होने पर कार्रवाई की गई। प्रोफेसर ने प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर सेवा बहाल कराने की मांग की है।

डॉ. भारद्वाज का कहना है कि उनकी नियुक्ति महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय की स्वीकृति के बाद 20 जून 2024 को हुई थी और उन्होंने 11 जुलाई 2024 को कार्यभार ग्रहण किया। उनका दावा है कि कॉलेज ने उन्हें पहचान पत्र जारी किया, जिसकी वैधता 30 जून 2027 तक है। इसके अलावा 20 मई 2026

को कॉलेज प्रशासन ने उन्हें उत्कृष्ट आचरण और कार्यनिष्ठा का प्रमाणित करते हुए चरित्र प्रमाणपत्र भी जारी किया।

प्रार्थना-पत्र में आरोप लगाया गया है कि इसके बावजूद अचानक बिना किसी आरोप, बिना कारण बताओ नोटिस (शो कॉज नोटिस), बिना विभागीय जांच और बिना सुनवाई का अवसर दिए उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। उन्होंने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों संबंधी नियमावली के विपरीत बताया है।

पुलिस से बचकर दिल्ली गए थे प्रोफेसर

डॉ. मोहित भारद्वाज ने कहा कि जंतर मंतर पर युवाओं की हक की लड़ाई में वे शामिल होने जा रहे थे लेकिन घर पर उन्हें नजरबंद करने की कोशिश की गई तब वे छत के कूदकर घर से निकले और धरना में शामिल हुए। जहां छात्रों पर लाठियां बरसाईं गईं। अगले दिन वे लौट आए तो प्रबंधक ने उन्हें निष्कासन पत्र थमा दिया। किसी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

डॉ. भारद्वाज ने कहा कि उनके खिलाफ कभी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई और न ही किसी जांच में कोई आरोप सिद्ध हुआ। उनका कहना है कि सेवा समाप्त होने से उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सेवा समाप्ति आदेश पर रोक लगाने की मांग

उन्होंने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने, जांच पूरी होने तक सेवा समाप्ति आदेश पर रोक लगाने, सेवा बहाल करने, बकाया वेतन व अन्य सेवा लाभ दिलाने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री से भी न्याय दिलाने की अपील की है।

कांवड़ यात्रा को लेकर बल्दीराय व धनपतगंज पुलिस अलर्ट

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुल्तानपुर। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से थाना बल्दीराय और थाना धनपतगंज पुलिस ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में दोनों थाना परिसरों में ग्राम प्रधानों, वरिष्ठ नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं सेवा शिविर संचालकों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। थाना बल्दीराय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी प्रभात सिंह, क्षेत्राधिकारी आशुतोष कुमार तथा थानाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने की। वहीं थाना धनपतगंज में थानाध्यक्ष अंजू मिश्रा ने बैठक का नेतृत्व किया। अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील स्थलों पर पुलिस तैनाती, यातायात प्रबंधन, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा सुविधाओं तथा श्रद्धालुओं की सुगमता सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक में मौजूद ग्राम प्रधानों और सेवा शिविर संचालकों से प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि या समस्या की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और यात्रा को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित बनाने के लिए सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करेंगे। धनपतगंज थाना क्षेत्र की बैठक में ग्राम प्रधानगण इंद्रपाल सिंह, ओमेंद्र सिंह बब्बू, विक्रम प्रताप सिंह शगोलूश, दिनेश पाठक, अरशद अली, प्रेमनाथ यादव शबाबाश, विजय शंकर राजू, शशिबल सिंह, संतोष पाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं सेवा शिविर आयोजक मौजूद रहे। अंत में थानाध्यक्ष अंजू मिश्रा ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए प्रशासन को निरंतर सहयोग देने की अपील की।

'राजा दशरथ की भी 3 रानियां थीं', तीन बहनों ने एक ही दूल्हे से की शादी, बवाल हुआ तो दिया ये तर्क

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अमरोहा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से शादी-ब्याह से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हसनपुर क्षेत्र के धौरिया गांव की रहने वाली तीन सगी बहनों ने एक कैमरामैन के साथ चामुंडा माता मंदिर में शादी कर ली। तीनों की उम्र 18 से 20 साल के बीच है। शादी का Video बुधवार शाम सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हिंदूवादी संगठनों ने इसे सनातन धर्म और सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन बताते हुए कड़ा विरोध जताया।

हालांकि, इस वीडियो की पुष्टि Tv9 भारतवर्ष नहीं करता। जानकारी के मुताबिक, धौरिया गांव की रहने वाली सरोज (20 वर्ष), सावित्री (19 वर्ष) और संतोष (18 वर्ष) ने 17 जुलाई को चामुंडा माता मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए।

श्यामपुरी गांव निवासी कैमरामैन विकास उर्फ विक्कू ने बारी-बारी से तीनों बहनों की मांग में सिंदूर भरा और तीनों ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हालांकि, इस दौरान दोनों पक्षों के परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। मंदिर प्रबंधक डॉ. शिवचरण दास ने स्पष्ट किया कि घटना के समय मंदिर में जीर्णोद्धार का काम चल रहा था और वहां कोई पुजारी मौजूद नहीं था।

शादी रचाने वाले चारों युवक-युवतियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी सक्रिय हैं। तीनों बहनें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बनाती हैं, जहां उनके इंस्टाग्राम पर 4.69 लाख और फेसबुक पर 84 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ी बहन सरोज बीटेक सेकंड ईयर की छात्रा है, जबकि बाकी दोनों ने 12वीं पास की है। दूल्हा विकास भी इसी साल 12वीं पास कर LLB की तैयारी कर रहा है और वो पिछले 6 महीने से उनकी रील्स में पति का किरदार निभाता था।

विरोध पर उतरीं दुल्हनें: 'राजा दशरथ की भी 3 रानियां थीं'

व्यापारी नेता मुकेश गुप्ता और स्थानीय हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद जब विवाद गहराया, तो तीनों बहनों ने वीडियो जारी कर अपना रुख साफ किया। बहनों का कहना है कि वे बचपन से साथ रही हैं। जब परिजनों ने अलग-अलग जगह शादी तय करने की कोशिश की, तो उन्होंने अलग होने के बजाय एक ही दूल्हे से एक साथ शादी करने का फैसला किया। विरोध करने वालों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "पहले जमाने में राजा दशरथ थे, जिनकी तीन रानियां थीं। क्या वह अपमान हो गया? हम तीनों बालिग हैं, अपनी मर्जी से खुश हैं, तो इसमें दूसरों को क्या आपत्ति है।"

पुलिस और स्थानीय प्रशासन की स्थिति

हसनपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी के अनुसार, शादी करने वाली युवतियों ने पुलिस को बताया है कि उन्होंने बालिग होने के नाते अपनी स्वेच्छा से मंदिर में विवाह किया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है।

श्री हनुमान बालाजी सेवा फाउंडेशन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत लगाए 700 पौधे

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। श्री हनुमान बालाजी सेवा फाउंडेशन, सुल्तानपुर द्वारा गुरुवार को जनपद प्रतापगढ़ के विकासखंड आसपुर देवसरा अंतर्गत ग्राम सोनपुरा में एक पेड़ माँ के नाम महा अभियान के तहत 700 पौधों का वृक्षारोपण एवं वितरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का नेतृत्व संस्था के पर्यावरण एवं जल संरक्षण विभाग के निदेशक वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने किया। सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक संस्था के सदस्यों ने पूरे गांव में घर-घर जाकर पौधे वितरित किए और प्रत्येक परिवार से अपनी माँ के सम्मान में एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए पौधारोपण भी कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. आशीष कुमार यादव ने की। शुभारंभ आसपुर देवसरा थानाध्यक्ष राकेश कुमार चौरसिया, उपनिरीक्षक

अवधराज यादव तथा सभासद शिवम सोनी ने पाँच-पाँच पौधे लगाकर किया। इस अवसर पर गांव के अनेक वरिष्ठ एवं गणमान्य नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए ग्रामीणों को पौधे वितरित किए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। संस्था प्रबंधन समिति बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार उपाध्याय की गरिमामयी उपस्थिति में यह विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संस्था के विभिन्न विभागों के निदेशक, सेवादाता, पत्रकार, शिक्षक, चिकित्सक, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला-पुरुष और युवाओं ने सहभागिता निभाई। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों ने सभी लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने, उनकी नियमित देखभाल करने तथा पर्यावरण संरक्षण को जन-जन का अभियान बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। सभी ने एक स्वर में संदेश दिया कि घर-घर पौधा, हर आँगन हरियाली तथा एक पेड़ माँ के नाम केवल एक अभियान नहीं, बल्कि प्रकृति और मातृसम्मान के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है।

गोरखपुर को 995 करोड़ रुपये की 14 विकास परियोजनाओं की सौगात

' विकास और विरासत साथ-साथ चल रहे हैं '

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अच्छी सरकारें विकास के साथ विरासत का भी सम्मान करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार गोरखपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। बिना किसी भेदभाव के सभी पात्र लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और बेहतर कानून व्यवस्था के कारण देश-विदेश के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।मुख्यमंत्री गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में 995 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 14 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने बताया कि 429 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ट्रांसपोर्ट नगर से पैडलेगंज तक 2,658 मीटर लंबे फ्लाईओवर तथा देवरिया बाईपास को जोड़ने वाले फोरलेन मार्ग का लोकार्पण किया गया है। इससे लगभग 50 लाख से एक करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा 271 करोड़ रुपये की लागत से पैडलेगंज-कसया मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का भी लोकार्पण हुआ, जो गोरखपुर को कुशीनगर से बेहतर ढंग से जोड़ेगा।मुख्यमंत्री ने बताया कि 104 करोड़ रुपये की लागत से वायुसेना स्टेशन में नए सैन्य परिसर तथा गुलरिहा थाने में नए बैरक का भी लोकार्पण किया गया। वहीं नंदानगर पुलिस चौकी से शमशेर गेट मार्ग पर अंडरपास, 50 करोड़ रुपये की लागत से विज्ञान संग्रहालय, मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास तथा राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया।उन्होंने कहा कि महिला छात्रावास में 500 कामकाजी महिलाओं के रहने की सुविधा उपलब्ध होगी, जबकि उत्कृष्टता केंद्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और ड्रोन प्रौद्योगिकी जैसे आधुनिक क्षेत्रों में छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर आधारभूत संरचना से आवागमन आसान हुआ है और समय की बचत के साथ विकास की गति भी तेज हुई है। अब गोरखपुर से लखनऊ की दूरी लगभग तीन घंटे, वाराणसी की दूरी ढाई घंटे और कुशीनगर की दूरी लगभग एक घंटे में तय की जा सकती है। गोरखपुर से 14 हवाई सेवाएं संचालित हो रही हैं तथा आधुनिक रेलवे सुविधाओं के साथ वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों से भी लोगों को लाभ मिल रहा है।उन्होंने कहा कि एक समय पूर्वी उत्तर प्रदेश इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझता था, लेकिन एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों तथा सरकार के प्रयासों से इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है। आसपास के जिलों में भी नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत हुई हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी गोरखपुर का रामगढ़ताल उपेक्षित और गंदगी से भरा रहता था, जबकि आज वह पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र बन चुका है। गुप्तेश्वर मंदिर का पुनरुद्धार कराया गया है और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास की दिशा में भी कार्य हो रहे हैं।उन्होंने कहा कि पहले अपराध और माफिया संस्कृति के कारण गीडा में कोई निवेश नहीं करना चाहता था, लेकिन अब बेहतर कानून व्यवस्था के कारण नए उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनसे 50 हजार युवाओं को रोजगार मिला है। बंद पड़े उद्योग दोबारा संचालित हुए हैं और किसानों को समय पर खाद एवं बीज उपलब्ध हो रहे हैं।मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

ऑपरेशन 'साइवज्र' में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, चार सरगना गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष अभियान 'साइवज्र' के तहत कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए विभूतिखंड क्षेत्र में संचालित फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 18 लाख 50 हजार रुपये नकद, 31 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, दो राउटर सहित बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार यह गिरोह अमेरिका के नागरिकों को फर्जी एप्पल ग्राहक सहायता सेवा के नाम पर ठगी का शिकार बना रहा था।यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर के निर्देशन, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार के पर्यवेक्षण तथा पुलिस उपायुक्त पूर्वी डॉ. दीक्षा शर्मा के मार्गदर्शन में की गई। अभियान का नेतृत्व अपर पुलिस उपायुक्त अमोल मुरकुट और सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखंड सौम्या पाण्डेय ने किया। सर्विलांस एवं अपराध शाखा पूर्वी जोन तथा थाना विभूतिखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने साइबर हाइट भवन के चौथे तल स्थित फ्लैट संख्या 420-ए में संचालित इस ठगी केंद्र का भंडाफोड़ किया।पुलिस के अनुसार 22 जुलाई की रात नियमित वाहन जांच के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि उक्त फ्लैट में विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर साइबर ठगी की जा रही है। सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर संयुक्त टीम गठित कर तड़के छापेमारी की गई। इलेक्ट्रॉनिक ताले से बंद फ्लैट का दरवाजा खोलकर तलाशी लेने पर वहां बड़ी संख्या में युवक-युवतियां विदेशी नागरिकों से बातचीत करते मिले।कार्रवाई में गिरोह के सरगना सूरज त्रिपाठी, उसके सहयोगी विवेक पाण्डेय, राहुल त्रिपाठी तथा तकनीकी विशेषज्ञ आकाश अरुण दत्ता उर्फ रिक्की को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार सूरज त्रिपाठी ने वर्ष 2012-13 में गुजरात के अहमदाबाद में एक कॉल सेंटर में काम करने के दौरान इस तरह की ठगी की कार्यप्रणाली सीखी थी। बाद में उसने अपने रिश्तेदारों और तकनीकी विशेषज्ञ की मदद से लखनऊ में यह गिरोह खड़ा किया।जांच में पता चला कि गिरोह ने इंटरनेट पर फर्जी एप्पल ग्राहक सहायता वेबसाइट बनाकर उसका व्यापक प्रचार कराया था। जब कोई अमेरिकी नागरिक एप्पल की सहायता सेवा खोजता था तो उसे सबसे पहले गिरोह का फर्जी दूरभाष नंबर दिखाई देता था।

अयोध्या मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य पर भ्रष्टाचार के आरोपों की उच्चस्तरीय जांच

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। अयोध्या मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार पर लगे वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति भी की गई है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा (डीजीएमई) नेहा शर्मा को पूरे मामले की विस्तृत जांच सौंपी गई है।डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अयोध्या मेडिकल कॉलेज में तैनाती के दौरान अवकाश पर रहते हुए भी सरकारी खरीद प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। आरोपों के अनुसार उन्होंने सरकारी खरीद के लिए जैम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल पर टेंडरों को स्वीकृति दी और करोड़ों रुपये के भुगतान संबंधी चेकों पर हस्ताक्षर भी किए, जबकि अवकाश पर जाने से पहले उन्होंने अपने पद का कार्यभार दूसरे अधिकारी को सौंप दिया था।यह शिकायत मेडिकल कॉलेज के पूर्व कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. सत्यजीत वर्मा की ओर से उपमुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा और महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को भेजे गए पत्र में की गई थी। शिकायत में कहा गया कि डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार ने बीमारी के कारण अवकाश पर रहने के बावजूद वित्तीय निर्णय लिए, जो नियमों के विपरीत हैं।शिकायत के अनुसार डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार ने चार जनवरी से 19 जनवरी 2023 तक अवकाश लिया था। अवकाश के दौरान उन्होंने अपना कार्यभार डॉ. पारस खरबंदा को सौंपा था। इसके बावजूद सात और 10 जनवरी 2023 को लगभग 84 लाख रुपये के जैम अनुबंधों को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा आठ से 10 जनवरी के बीच 17 चेकों पर हस्ताक्षर कर लगभग 1 करोड़ 28 लाख 90 हजार 990 रुपये का भुगतान कराया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस अवधि में कुल 2.12 करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी धन का व्यय किया गया।शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जब संबंधित अधिकारी अवकाश पर थे और कार्यभार दूसरे अधिकारी के पास था, तब उनके द्वारा वित्तीय निर्णय लेना और भुगतान संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

नौकरी का झांसा देकर बैंक खाते खुलवाने वाले साइबर गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। कमिश्नरेट लखनऊ की हजरतगंज पुलिस और साइबर टीम ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी में करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में दो पुरुष और एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 23 एटीएम कार्ड, 13 पासबुक, 9 चेकबुक और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े फरार आरोपियों और विदेशी कनेक्शन की तलाश में जुटी है।पुलिस के अनुसार उपनिरीक्षक इंद्रपाल सिंह फौजदार की तहरीर पर थाना हजरतगंज में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच के लिए पुलिस उपायुक्त मध्य के निर्देशन में साइबर और अपराध शाखा की संयुक्त टीम गठित की गई।जांच के दौरान पुलिस ने बदायूं निवासी वरुण कांत शर्मा, फर्रुखाबाद निवासी प्रेम कुमार उर्फ विमल तथा एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में गिरोह के दो अन्य सदस्यों अमित और दिनेश सिंह के नाम सामने आए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी आसपास के शहरों और गांवों के बेरोजगार लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनके नाम से विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाते थे। इसके बाद उनसे एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, सिम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग की उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड सहित बैंक खातों की पूरी जानकारी अपने कब्जे में ले लेते थे।

लखनऊ पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का किया पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी की हजरतगंज पुलिस और साइबर टीम ने अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरोह नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों के बैंक खाते खुलवाता था और उनके एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, सिम कार्ड तथा इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी हासिल कर चीनी साइबर ठगों तक पहुंचाता था। इन खातों में साइबर अपराध से प्राप्त धनराशि जमा कराई जाती थी, जिसे निकालकर डिजिटल मुद्रा (यूएसडीटी) में परिवर्तित कर विदेशी नेटवर्क तक पहुंचाया जाता था।पुलिस के अनुसार उपनिरीक्षक इंद्रपाल सिंह फौजदार की तहरीर पर थाना हजरतगंज में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले के खुलासे के लिए पुलिस उपायुक्त मध्य के निर्देशन में साइबर और अपराध शाखा की संयुक्त टीम गठित की गई।जांच के दौरान पुलिस ने वरुण कांत शर्मा, प्रेम कुमार उर्फ विमल तथा एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि गिरोह के दो अन्य सदस्य अमित और दिनेश सिंह पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहे थे। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।पुलिस के अनुसार गिरोह ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के बेरोजगार लोगों को नौकरी का लालच देकर उनके नाम से विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाता था। इसके बाद उनसे एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, सिम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग की पूरी जानकारी अपने कब्जे में ले ली जाती थी। इन बैंक खातों का विवरण टेलीग्राम के माध्यम से चीनी साइबर ठगों को भेजा जाता था। जांच में पता चला कि साइबर ठगी से प्राप्त बड़ी धनराशि इन खातों में जमा की जाती थी।

अनंतम–2026' में महिला उद्यमिता और भारतीय हस्तशिल्प का शानदार संगम

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। फिक्की फ्लो लखनऊ चैप्टर की ओर से होटल हयात रीजेंसी में चेयरपर्सन सिमरन साहनी के नेतृत्व में लाइफस्टाइल एवं महिला उद्यमिता प्रदर्शनी 'अनंतम-2026' के चौथे संस्करण का भव्य आयोजन किया गया। देशभर से आई महिला उद्यमियों, पारंपरिक कारीगरों और प्रतिष्ठित लाइफस्टाइल ब्रांड्स की भागीदारी से सजी यह प्रदर्शनी पूरे दिन आकर्षण का केंद्र रही।प्रदर्शनी का उद्घाटन फिक्की फ्लो की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा गर्ग ने किया। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति में महिलाओं की भागीदारी जितनी मजबूत होगी, देश उतनी ही तेजी से आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेगा। उन्होंने कहा कि 'अनंतम' जैसे आयोजन महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, नए बाजार और व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि फिक्की फ्लो महिलाओं को अवसर, संसाधन और मंच उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है।फिक्की फ्लो लखनऊ की चेयरपर्सन सिमरन साहनी ने कहा कि 'अनंतम' केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि महिला उद्यमिता, भारतीय कारीगरी और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का उत्सव है। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य शहरी महिला उद्यमियों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाशाली महिलाओं और पारंपरिक कारीगरों को भी समान अवसर उपलब्ध कराना है। उनके अनुसार, जब महिलाओं को उचित मंच और बाजार मिलता है तो वे न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती हैं।उन्होंने बताया कि इस वर्ष देशभर से 50 से अधिक चयनित ब्रांड्स ने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। फैशन, डिजाइनर परिधान, हथकरघा, हस्तनिर्मित वस्त्र, आभूषण, गृह सज्जा, स्वास्थ्य उत्पाद, जैविक खाद्य सामग्री, हस्तशिल्प, सजावटी वस्तुएं और प्रीमियम जीवनशैली से जुड़े उत्पादों की आकर्षक श्रृंखला ने आगंतुकों का ध्यान खींचा। बड़ी संख्या में शहरवासियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, उद्यमियों और खरीदारों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा महिला उद्यमियों के उत्पादों की सराहना की।इस वर्ष प्रदर्शनी की विशेषता समावेशी आर्थिक सशक्तिकरण रही। फिक्की फ्लो लखनऊ ने विभिन्न राज्यों से आए पारंपरिक कारीगरों को रियायती दरों पर स्टॉल उपलब्ध कराए। वहीं संगठन द्वारा गोद लिए गए गांवों की महिलाओं तथा ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़ी महिला लाभार्थियों को अपने हस्तनिर्मित उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए निःशुल्क स्टॉल प्रदान किए गए।

बीबीएयू के वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता, पर्यावरण–अनुकूल दवा निर्माण तकनीक को मिला भारतीय पेटेंट

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ के रसायन विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने दवा निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विभाग के डॉ. जवाहर लाल जाट के वैज्ञानिक निर्देशन एवं मार्गदर्शन में शोधार्थी डॉ. पुनीत कुमार और उनकी शोध टीम ने प्राथमिक अमाइन के निर्माण की एक नई, सरल और पर्यावरण-अनुकूल तकनीक विकसित की है। इस नवाचार को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने भारतीय पेटेंट संख्या-595951 के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की है।विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने इस उपलब्धि पर शोध दल को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है और इससे संस्थान की वैज्ञानिक पहचान और मजबूत होगी।डॉ. जवाहर लाल जाट ने इस शोध की संकल्पना तैयार करने, अनुसंधान की रूपरेखा बनाने, नई संश्लेषण विधि विकसित करने और वैज्ञानिक मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं डॉ. पुनीत कुमार ने शोधार्थी के रूप में प्रयोगात्मक अनुसंधान, प्रक्रिया के विकास, अनुकूलन और सत्यापन का कार्य किया। दोनों के संयुक्त प्रयासों से विकसित धातु-मुक्त तकनीक को अब भारतीय पेटेंट प्राप्त हो गया है।विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान समय में नई दवाओं के विकास में नाइट्रोजन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक पिछले लगभग दस वर्षों में अमेरिका के औषधि नियामक प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नई दवाओं में लगभग 82 प्रतिशत दवाओं में कम से कम एक नाइट्रोजन परमाणु मौजूद है। कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियों तथा एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण में नाइट्रोजन युक्त यौगिकों की अहम भूमिका होती है।अब तक प्राथमिक अमाइन के निर्माण के लिए पैलेडियम, निकेल, तांबा और लौह जैसी महंगी धातुओं का उपयोग किया जाता रहा है। इन प्रक्रियाओं में अधिक लागत, जटिल निर्माण प्रणाली, धातु अवशेषों से उत्पाद के दूषित होने और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। विशेष रूप से औषधि उद्योग में धातु के सूक्ष्म अवशेष भी गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती माने जाते हैं।बीबीएयू के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई तकनीक में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध एरिल बोरोनिक अम्ल को बिना किसी धातु उत्प्रेरक के सीधे प्राथमिक अमाइन में परिवर्तित किया जाता है। पूरी प्रक्रिया एक ही चरण में सामान्य परिस्थितियों में पूरी हो जाती है। इससे न केवल उत्पादन प्रक्रिया सरल और सुरक्षित बनती है, बल्कि अधिक शुद्ध उत्पाद भी प्राप्त होता है तथा धातु अवशेषों की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि यह तकनीक पर्यावरण संरक्षण और हरित रसायन विज्ञान के सिद्धांतों के अनुरूप मानी जा रही है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तकनीक को औद्योगिक स्तर पर अपनाया जाता है तो दवाओं के निर्माण की लागत में कमी आ सकती है। साथ ही रासायनिक अपशिष्ट और औद्योगिक प्रदूषण भी घटेगा। यह तकनीक औषधि, कृषि रसायन और विशेष रसायन उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक होगी।

स्वयं सहायता समूहों से बदल रही ग्रामीण महिलाओं की तस्वीर, नीतू कुंडू बनीं आत्मनिर्भरता की मिसाल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के माध्यम से व्यापक स्तर पर अभियान चला रही है। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के जरिए लाखों महिलाएं बचत, स्वरोजगार और उद्यमिता से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे रही हैं।इसी कड़ी में ग्राम मोहम्मदपुर धैदा की निवासी नीतू कुंडू की कहानी महिला सशक्तिकरण का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आई है। पार्वती महिला ग्राम संगठन और महिला शक्ति क्लस्टर धैदा से जुड़ी नीतू ने वर्ष 2021 में 'राधिका स्वयं सहायता समूह' की सदस्यता लेकर आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया। उस समय उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था, लेकिन समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने बचत, वित्तीय अनुशासन और स्वरोजगार का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

संक्षेप

सपा विधायक आलम बदी के निधन पर अखिलेश यादव ने जताया शोक, बताया अपूरणीय क्षति

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक आलम बदी (90 वर्ष) के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।अखिलेश यादव ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आलम बदी बेहद सादगी पसंद, ईमानदार और निष्ठावान नेता थे। सादगी उनकी सबसे बड़ी पहचान थी और उन्होंने लंबे समय तक जनता की निस्वार्थ सेवा की।उन्होंने कहा कि आलम बदी के निधन से समाजवादी पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। उनका राजनीतिक और सामाजिक योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा।आलम बदी आजमगढ़ जिले की निजामाबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वर्ष 1996, 2002, 2012, 2017 और 2022 में विधायक निर्वाचित हुए थे। क्षेत्र में उनकी सादगी, जनसंपर्क और जनता के प्रति समर्पण के कारण उन्हें एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में जाना जाता था।

लखनऊ में निर्माणाधीन भवन की लिफ्ट गिरने से चार मजदूर घायल, तीन की हालत गंभीर

लखनऊ। राजधानी के महानगर थाना क्षेत्र स्थित विज्ञानपुरी के शालीमार गैलेंट में निर्माणाधीन भवन में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। भवन में प्लास्टर का कार्य कर रहे मजदूरों को ले जा रही लिफ्ट अचानक टूटकर बेसमेंट में गिर गई, जिससे उसमें सवार चार मजदूर घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया।पुलिस के अनुसार घटना गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे हुई। निर्माण कार्य के दौरान लिफ्ट में सवार चार मजदूर प्लास्टर का काम कर रहे थे। इसी दौरान लिफ्ट टूटकर सीधे बेसमेंट में जा गिरी, जिससे चारों मजदूर घायल हो गए।पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल नीरा हॉस्पिटल, लखनऊ में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार घायलों में तीन मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि एक मजदूर को मामूली चोट लगी है। राहत की बात यह है कि सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।घायलों की पहचान छोटू कुमार (28 वर्ष), सुरेन्द्र कुमार (45 वर्ष), निक्कू (24 वर्ष) और मोनू (25 वर्ष) के रूप में हुई है। सभी मजदूर बिहार के समस्तीपुर जिले के निवासी हैं और निर्माण कार्य में लगे हुए थे।पुलिस ने बताया कि हादसे में निर्माण स्थल पर कार्य कर रहे अन्य सभी मजदूर सुरक्षित हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है और मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

कांग्रेस मुख्यालय में मनाई गई लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का लिया संकल्प

लखनऊ। महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती गुरुवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय ने की। इस अवसर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दोनों महान विभूतियों के चित्रों पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजय राय ने कहा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे महानायक हैं, जिनका साहस, त्याग और राष्ट्रप्रेम आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि लोकमान्य तिलक का उद्घोष स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है स्वतंत्रता आंदोलन का मार्गदर्शक बना, जबकि चंद्रशेखर आजाद के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान ने देश के युवाओं में देशभक्ति की ऐसी अलख जगाई, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया।अजय राय ने कहा कि वर्तमान समय में देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं, संविधान, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों और संघर्ष के मार्ग पर चलने का संकल्प लेने की आवश्यकता है।कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प भी लिया।इस अवसर पर कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री डॉ. सी.पी. राय, प्रो. विनोद चंद्रा, सुरेंद्र यादव, प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता, सलमान बशर, रजनीश यादव, अब्दुल्ला शेर खान, जयंत गौतम, अजीत मौर्य, एस.बी. मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार, लखनऊ पुलिस की त्वरित कार्रवाई

लखनऊ। राजधानी के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने घटना दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।पुलिस के अनुसार पीड़िता ने थाना हुसैनगंज में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी गोविन्द ने उसे शादी का झांसा दिया। आरोप है कि आरोपी ने शीतल पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी।पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना हुसैनगंज में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की।मुखबिर की सूचना पर थाना हुसैनगंज पुलिस टीम ने आरोपी गोविन्द (24 वर्ष) को उसके किराये के मकान सफदरगंज, लाल कुआं, कैसरबाग से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का स्थायी निवास ग्राम तुलसीपुर माझा, थाना नवाबगंज, जनपद गोंडा बताया गया है।पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य थानों और जनपदों से जुटाई जा रही है।इस कार्रवाई में थाना हुसैनगंज के प्रभारी निरीक्षक शिवमंगल सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिंह यादव, उपनिरीक्षक सुहैल अहमद, मुख्य आरक्षी आशीष शुक्ला तथा आरक्षी अजय कुमार शामिल रहे।

भारत से टकराने की जिद बड़ी भारी पड़ती है, 'हिंदुस्तान के हिस्से का बिल' भी भर रहा है पाकिस्तान!

सीमापार आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बना चुके पाकिस्तान की आज ऐसी दुर्गति हो चुकी है कि वह भारत के खिलाफ साजिश रचने की कीमत भी अपनी जेब से चुका रहा है। दरअसल, सिंधु जल संधि को लेकर भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर घेरने की नाकाम कोशिश में इस्लामाबाद न केवल अपनी ओर से खर्च उठा रहा है, बल्कि भारत के हिस्से का व्यय भी खुद अदा कर रहा है। यानी जिस देश को वह कटघरे में खड़ा करना चाहता है, उसी का बिल भी उसे भरना पड़ रहा है। यह दृश्य पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली, कूटनीतिक बेबसी और बौखलाहट का सबसे बड़ा प्रमाण है। दुनिया के सामने भारत को घेरने निकला पाकिस्तान आज अपनी ही बनाई चाल में फंसकर उपहास का पात्र बन गया है।

हम आपको बता दें कि सिंधु जल संधि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत छह नदियों के जल के बंटवारे का ढांचा तय किया गया था। दशकों तक भारत ने संधि का पूरी निष्ठा से पालन किया, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को संरक्षण देता रहा। पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने साफ संदेश दिया कि जब तक पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद का विश्वसनीय और स्थायी रूप से परित्याग नहीं करता, तब तक सामान्य स्थिति की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी क्रम में भारत ने संधि से जुड़ी कार्यवाहियों में अपनी भागीदारी स्थगित कर दी। भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। नई दिल्ली का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियां 1960 जैसी नहीं रहीं। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी, ऊर्जा की आवश्यकता, नई प्रौद्योगिकी और सबसे बढ़कर पाकिस्तान प्रायोजित सीमापार आतंकवाद ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। ऐसे में संधि की समीक्षा और नए सिरे से विचार स्वाभाविक आवश्यकता है।

इसके विपरीत पाकिस्तान हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस मध्यस्थता प्रक्रिया से वह भारत पर दबाव बनाना चाहता है, उसी का पूरा आर्थिक बोझ भी उसे स्वयं उठाना पड़ रहा है। यह उस कूटनीतिक दिवालियेपन का प्रतीक है जिसमें पाकिस्तान दुनिया के सामने अपनी दलीलें जीवित रखने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार दिखाई देता है।

सच्चाई यह भी है कि सिंधु जल संधि से दशकों तक सबसे बड़ा लाभ पाकिस्तान को मिला। भारत, ऊपरी प्रवाह वाला देश होने के बावजूद, संधि की कठोर शर्तों का पालन करता रहा। अनेक विशेषज्ञ लंबे समय से यह प्रश्न उठाते रहे हैं कि यह व्यवस्था भारत के हितों के अनुरूप नहीं रही। इसके बावजूद भारत ने जिम्मेदार राष्ट्र का परिचय दिया। लेकिन जब पड़ोसी देश आतंकवादियों को शरण दे, प्रशिक्षण दे और भारत के निर्दोष नागरिकों का रक्त बहाने वालों को संरक्षण प्रदान करे, तब केवल सद्भावना के आधार पर संबंध नहीं चल सकते।

पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शोर मचाने से वास्तविकता नहीं बदलती। आतंकवाद और बातचीत, आतंकवाद और सहयोग, आतंकवाद और विश्वास, ये तीनों एक साथ नहीं चल सकते। यदि इस्लामाबाद यह सोचता है कि वह एक ओर आतंकियों को पालता रहेगा और दूसरी ओर जल समझौतों तथा वैश्विक संस्थाओं की आड़ लेकर भारत पर दबाव बनाएगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है।

भारत ने बार-बार संयम दिखाया है, लेकिन संयम को कमजोरी समझना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, जल हितों और संप्रभु अधिकारों से किसी प्रकार का समझौता करने वाला नहीं है। यदि पाकिस्तान वास्तव में क्षेत्र में शांति चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी धरती से संचालित सीमापार आतंकवाद की फैक्ट्रियों पर स्थायी ताला लगाना होगा। बहरहाल, पाकिस्तान के नीति-निर्माताओं के लिए यह घटनाक्रम स्पष्ट संदेश है। जो देश आज भारत का हिस्सा भी अपनी जेब से भरने को विवश है, उसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था, अपने शासन और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए। भारत को धमकियों या अंतरराष्ट्रीय मंचों की कार्यवाहियों से झुकाया नहीं जा सकता। भारत की ओर से संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि पाकिस्तान ने सीमापार आतंकवाद को हमेशा के लिए बंद नहीं किया, तो उसे केवल आर्थिक ही नहीं, कूटनीतिक, सामरिक और रणनीतिक स्तर पर भी और बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। शांति का मार्ग आतंकवाद छोड़ने से होकर जाता है, न कि दुनिया भर में शिकायतों का पुलिंदा लेकर घूमने से। समय रहते पाकिस्तान को यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी, क्योंकि नया भारत अपनी सुरक्षा और अपने राष्ट्रीय हितों पर किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है।

सोनम वांगचुक और गणतंत्र की नैतिक परीक्षा

सतीश झा

राज्य के भीतर कहीं न कहीं ऐसा दरवाज़ा अवश्य होना चाहिए, जहाँ किसी नागरिक की गंभीर और सार्वजनिक महत्व की शिकायत इसलिए सुनी जाए कि वह न्यायसंगत है

सोनम वांगचुक का आंदोलन एक प्रश्नपत्र से आगे बढ़ जाता है। वे केवल परीक्षा प्रणाली की जवाबदेही नहीं माँग रहे। वे उस सोच पर प्रश्न उठा रहे हैं, जिसने शिक्षा को छँटनी की मशीन बना दिया है। उनके भीतर छिपा प्रश्न कहीं बड़ा है—क्या भारत अपने युवाओं का भविष्य बना रहा है, या केवल उनका क्रम तय कर रहा है? यही प्रश्न उनके पूरे सार्वजनिक जीवन को समझने की कुंजी भी है।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी विफलता तब नहीं होती, जब सरकार कोई गलत फैसला ले। सरकारें गलतियाँ करती हैं और उन्हें सुधारने का अवसर भी होता है। असली विफलता तब होती है, जब किसी नागरिक को अपनी बात सुनाने के लिए अपने शरीर को ही आख़िरी तर्क बनाना पड़े। किसी भी गणतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सत्ता किसी नागरिक की बात तब सुने, जब डॉक्टर चेतावनी दे चुके हों, अदालत हस्तक्षेप कर चुकी हो और उसका शरीर जवाब देने लगा हो। राज्य के भीतर कहीं न कहीं ऐसा दरवाज़ा अवश्य होना चाहिए, जहाँ किसी नागरिक की गंभीर और सार्वजनिक महत्व की शिकायत इसलिए सुनी जाए कि वह न्यायसंगत है, इसलिए नहीं कि वह मरने के कगार पर पहुँच गया है। 18 जुलाई 2026 को सोनम वांगचुक को दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इक्कीस दिन के उपवास ने उनके शरीर को बुरी तरह तोड़ दिया था। उन्होंने 28 जून को आमरण अनशन शुरू किया था। उनका संघर्ष किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था। वे उन लाखों युवाओं के पक्ष में खड़े थे, जिनका विश्वास प्रश्नपत्र लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं की अव्यवस्था ने तोड़ दिया। दिल्ली हाईकोर्ट को भी उनके स्वास्थ्य की निगरानी का निर्देश देना पड़ा। एक ऐसा प्रश्न, जिसका उत्तर लोकतांत्रिक संवाद से दिया जाना चाहिए था, धीरे-धीरे एक नागरिक की शारीरिक सहनशक्ति और राज्य की संवेदनशीलता की परीक्षा बन गया। पहली नज़र में यह विवाद केवल प्रश्नपत्र लीक का दिखाई देता है। परीक्षा रद्द हुई, अनियमितताओं के आरोप लगे, जवाबदेही की माँग उठी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक की आवाज़ पहुँची। यह सब गंभीर है, क्योंकि प्रश्नपत्र लीक केवल परीक्षा में धांधली नहीं है। यह उस भरोसे की हत्या है, जिसके सहारे करोड़ों युवा वर्षों तक तैयारी करते हैं। राज्य उनसे वादा करता है कि मेहनत और योग्यता का निष्पक्ष मूल्यांकन होगा। प्रश्नपत्र लीक उसी वादे का विश्वासघात है। लेकिन यदि हम यहीं रुक जाएँ, तो सबसे बड़ा प्रश्न छूट जाएगा।

मान लीजिए भारत की हर परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष हो जाए। कहीं कोई प्रश्नपत्र लीक न हो, कोई नकल न हो, कोई भ्रष्टाचार न हो। क्या तब हमारी शिक्षा व्यवस्था सफल मानी जाएगी?

क्योंकि परीक्षा और शिक्षा एक ही चीज़ नहीं हैं।

परीक्षा चुनती है, शिक्षा बनाती है। परीक्षा यह तय करती है कि सौ उम्मीदवारों में एक कौन आगे जाएगा। शिक्षा का दायित्व यह है कि सौ में सौ अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच सकें। भारत ने इन दोनों के बीच का अंतर धीरे-धीरे भुला दिया है। हमने शिक्षा को प्रतियोगी परीक्षा का पर्याय बना दिया है। हर समस्या का समाधान हमें परीक्षा सुधार में दिखाई देता है—सुरक्षा बढ़ाइए, कैमरे लगाइए, डिजिटल निगरानी कीजिए, प्रश्नपत्र और सुरक्षित कर दीजिए। यह सब आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त आज अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाएँ ज्ञान का उत्सव नहीं, अवसरों की कमी का प्रबंधन बन गई हैं। जब एक सीट के लिए हजारों उम्मीदवार खड़े हों, तो परीक्षा योग्यता जितनी नहीं, दुर्लभ अवसरों की चौकीदारी उतनी करती है। वह कुछ लोगों को सफलता का प्रमाणपत्र देती है और बाकी लाखों को असफलता का बोझ। फिर व्यवस्था बड़ी सहजता से कह देती है कि दूसरा उम्मीदवार अधिक योग्य था। बहुत कम लोग यह पूछते हैं कि सौ योग्य युवाओं के लिए अवसर केवल एक ही क्यों था।

धीरे-धीरे व्यवस्था की विफलता व्यक्ति की विफलता में बदल दी जाती है। असफल छात्र से कहा जाता है कि वह और मेहनत करे, बेहतर कोचिंग ले, एक बार फिर प्रयास करे। लेकिन राज्य से यह नहीं पूछा जाता कि उसने पर्याप्त अवसर क्यों नहीं बनाए। शिक्षा का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को सक्षम बनाना है; प्रतियोगी परीक्षा का उद्देश्य उनमें से कुछ को अलग कर देना। यही दोनों के बीच का सबसे बुनियादी अंतर है।

यहीं से सोनम वांगचुक का आंदोलन एक प्रश्नपत्र से आगे बढ़ जाता है। वे केवल परीक्षा प्रणाली की जवाबदेही नहीं माँग रहे। वे उस सोच पर प्रश्न उठा रहे हैं, जिसने शिक्षा को छँटनी की मशीन बना दिया है। उनके भीतर छिपा प्रश्न कहीं बड़ा है—क्या भारत अपने युवाओं का भविष्य बना रहा है, या केवल उनका क्रम तय कर रहा है? यही प्रश्न उनके पूरे सार्वजनिक जीवन को समझने की कुंजी भी है।

सोनम वांगचुक ने अपनी यात्रा विरोध से नहीं, निर्माण से शुरू की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने 1988 में लद्दाख में स्श्वष्टरूह्रु की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें लगा कि वहाँ के बच्चे प्रतिभा के अभाव में नहीं, बल्कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था के कारण असफल घोषित किए जा रहे हैं, जो उनकी भाषा, उनके भूगोल और उनके जीवन से बिल्कुल अनजान है। बाद में उन्होंने जल संरक्षण, निष्क्रिय सौर ऊर्जा, टिकाऊ निर्माण और आइस स्तूप जैसी तकनीकों पर काम किया। उनका तरीका हमेशा एक जैसा रहा—पहले समस्या को समझो, फिर उसका समाधान विकसित करो और अंत में स्वयं उसकी जिम्मेदारी उठाओ। इसी काम ने उन्हें 2018 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिलाया।

यही कारण है कि सोनम वांगचुक का नैतिक प्रभाव केवल इसलिए नहीं है कि वे सरकार की आलोचना करते हैं। भारत में सरकारों की आलोचना करने वालों की कमी नहीं है। उनका महत्व इसलिए है कि उन्होंने पहले काम किया, फिर बोलना शुरू किया। शिक्षा, पर्यावरण, स्थानीय समाज और लोकतांत्रिक जवाबदेही—पहली नज़र में ये अलग-अलग विषय लगते हैं, लेकिन इनके पीछे एक ही विचार काम करता है—विकास मनुष्य के लिए होना चाहिए, मनुष्य विकास के लिए नहीं। इसीलिए उनके हर विचार से सहमत होना आवश्यक नहीं, लेकिन उन्हें गंभीरता से सुनना आवश्यक है। लोकतंत्र में नैतिक अधिकार पद, प्रसिद्धि या लोकप्रियता से नहीं मिलता। वह जीवन भर किए गए काम से अर्जित होता है। यहीं से असली प्रश्न शुरू होता है। क्या भारतीय गणतंत्र आज भी अपने सबसे गंभीर नागरिकों को बिना उनकी जान जोखिम में डाले सुनने की क्षमता रखता है? सोनम वांगचुक का महत्व केवल उनके काम में नहीं, बल्कि उस तरह की नागरिकता में है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। वे किसी राजनीतिक दल के नेता नहीं हैं। चुनाव नहीं लड़ते। सत्ता प्राप्त करना उनका लक्ष्य नहीं रहा। फिर भी वे बार-बार राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ जाते हैं। इसका कारण उनकी लोकप्रियता नहीं, उनकी सार्वजनिक विश्वसनीयता है। उन्होंने शिक्षा पर काम किया, पर्यावरण पर किया, लद्दाख के स्थानीय समाज के साथ किया।

व्यंग्य

ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की घटती मौजूदगी

अध्ययन के दौरान 26 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 400 ग्राम पंचायतों में करीब 7,800 लोगों के बीच सर्वेक्षण हुआ। उससे सामने आया कि ग्राम सभा की बैठकों लोगों की मौजूदगी घटती चली गई है।

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की एक ताजा रिपोर्ट का सार है कि ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज व्यवस्था नाकाम होने के कगार पर है। रिपोर्ट- राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राम सभाओं में निम्न भागीदारी- शीर्षक से जारी हुई है। कहा गया है कि यह अध्ययन स्थानीय स्व-शासन पर देश के सबसे बड़े जमीनी आकलनों में से एक है। इसके तहत 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 400 ग्राम पंचायतों में करीब 7,800 लोगों के बीच सर्वेक्षण किया गया। इससे सामने आया कि ग्राम सभा की बैठकों लोगों की मौजूदगी लगातार घटती चली गई है। आधे से ज्यादा लोगों ने कहा कि बैठकों में शामिल न होने की वजह रोजगार और कमाई से जुड़ी हैं। कामकाजी वर्ग के लिए काम-धंधा छोड़कर बैठक में आना कठिन होता है।

फिर बैठकों में स्थानीय रसूखदार लोगों का ही दबदबा बना रहता है। रिपोर्ट में जिक्र है कि ग्राम सभाएं स्थानीय मुद्दों की पहचान करने में लगभग 13 प्रतिशत समय लगाती हैं, लेकिन राजस्व बढ़ाने के उपायों पर केवल चार फीसदी समय खर्च करती हैं। चूंकि केंद्रीय अनुदान से मिलने वाला पैसा काफी हद तक पहले से तय केंद्रीय प्राथमिकताओं (जैसे जल जीवन मिशन) से जुड़ा होता है, इसलिए स्थानीय जरूरतों के मुताबिक योजना पर अमल लगभग नामुमकिन ही बना रहता है। इस रूप में पंचायती राज संस्थाएं केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसी बन कर रह गई हैं। जबकि 73वें और 74वें संविधान में परिकल्पना उन्हें शासन के तीसरे स्तर के रूप में स्थापित करने की गई थी।

वैसे, यह आरंभ में ही स्पष्ट हो गया था कि पंचायती संस्थाओं के लिए वित्त आयोग से तय अपना बजट और अपनी नौकरशाही नहीं होगी, तो उनका यही हाल होगा। फिर भी इस ओर कोई पहल नहीं हुई। इस सिलसिले में अक्सर उल्लेख होता है कि अमेरिका जैसी पूंजीवादी और चीन जैसी समाजवादी व्यवस्थाओं में एकमात्र समानता शासन का कारगर विकेंद्रीकरण है। दोनों जगहों पर इस नीति के सकारात्मक परिणाम जग-जाहिर हैं। मगर भारत में केंद्र हो या राज्य, अपने अधिकार क्षेत्र में कटौती के लिए तैयार नहीं हैं। नतीजा, ताजा रिपोर्ट में शामिल विलाप है।

ब्लॉग

आगे कुँआ, पीछे मोदी

शंकर शरण

बेचारे हिन्दू दोहरी चोट झेल रहे हैं — संघ-परिवार का विश्वासघात और ब्लैकमेलिंग। क्या इस से आगे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, राजा बाबू ने सब प्रबंध कर लिया है। कहीं कोई छिद्र नहीं छोड़ा। चाहे संवैधानिक संस्थाओं, रेफरियों पर धब्बा लगता रहे। लिहाजा चुनावी फुटबॉल का नेशनल कप वही जीतते रहेंगे। बाकी इंडिया बस वाचता रहेगा! यह सब समाज को खोखला करते जाने की कीमत पर। बस कप हाथ में रहे, चाहे वास्तविक खेल केवल कागजी हो जाए।

एक अर्थ में यह संघ-परिवार का ही तर्क है। तेईस साल पहले, 2003 में इसे 'टीना (ञ्जड्ढह्र) कहा गया था — देयर इज नो अल्टरनेटिव — यानी, भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए, ऐ देशवासियो, भाजपा को समर्थन दो! क्योंकि और किसे दोगे? कांग्रेस नेता को तो बोलना भी नहीं आता, कागज देख-देख पढ़ती है। बल्कि, जब तक यह बेचारी कांग्रेस की नेता है — तब तक भाजपा को चिन्ता की भी जरूरत नहीं! कौन 'इंडिया शाइनिंग कर देने वाली भाजपा के बदले उस अटपटी कांग्रेस नेता को समर्थन देगा!

उक्त दलील 2004 के आरंभ तक इतनी दुहराई जाती रही थी, कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस वर्ष चुनाव से पहले कहा ₹चुनाव में क्या होना है; कोई कांप्टीशन ही नहीं है!

तब से भाजपा नेता काफी बदल गये हैं। कुछ मामलों में अधिक होशियार, कुछ मामलों में और माशाअल्लाह। अगला चुनाव जीतने वाली सब तकनीकी कमियाँ इन्होंने दूर कर ली हैं, जिन पर किसी का ध्यान भी नहीं गया था। जिस में मुख्य यह कि मैच जीतने का सब से सुरक्षित तरीका है कि सामने कोई टीम ही न हो। यानी, सामने टीम न बनने दो! प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों में किसी को लुभा कर, किसी को डरा कर, किसी को फँसा कर, उस टीम से दूर रखो जो चुनौती दे सकती हो। अपनी टीम में भी कैप्टन बनने योग्य खिलाड़ियों को बाहर कर दो। बस, घुमा-फिरा कर वह वातावरण बनानाः जिसे 'टीना कह लीजिए — कि भई और है कौन जिसे समर्थन दोगे!

दूसरी ओर, माशाअल्लाह यह कि दस वर्ष पहले संघ-भाजपाइयों द्वारा जो ऊँची-ऊँची उपलब्धि की बात कही जाती थी, अब उन में किसी का नाम तक नहीं लिया जाता। भ्रष्टाचार-मुक्ति, स्वदेशी आर्थिकी, दुनिया में प्रभाव, चीन को झुकाना, और — एक आकस्मिक नया लक्ष्यः 'कांग्रेस मुक्त भारत और 'माँ-बेटे को जेल पहुँचाना — यह सब अब भक्त भी नहीं दुहराते।

पूरे देश ने देखा कि चीन कहाँ है, और अपने राम क्या हैं। बगल बंगलादेश में हिन्दुओं का कत्ल, अपमान, मंदिर-ध्वंस होता रहा है — और अपने राजा के मुँह से एक शब्द तक नहीं निकला। जबकि कांग्रेस राज में बंगलादेश के हिन्दुओं के लिए संघ-परिवार यहाँ सरकार से दर्जन भर माँगे करता था। उस में संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा उठाना भी था! यह उदाहरण है कि सारी बातें हवाबाजी थी। इसीलिए उन के कार्यकर्ता भी अब चुप हैं। सब जान चुके कि इन तिलों में तेल नहीं। कुछ विषयों में स्थिति पहले से बदतर हुई है। शिक्षा क्षेत्र इस का खुला उदाहरण है। विशिष्ट संस्थानों की स्वायत्तता भी छिन गई है। विद्या, विद्यार्थी, अध्यापक, स्नातक, सर्टिफिकेट या अवार्ड की गुणवत्ता का जिम्मेदार कोई नहीं है। महत्वपूर्ण अकादमियों में भी विद्वानों के स्थान पर मुंशी बिठा दिये गये हैं। ताकि अपनी टीम की जयकार करने, जुमले दोहराने वालों की संख्या बढ़े। बस। शिक्षा का जो हो, कुर्सी अपने हाथ रहे। यह फाउल खेलने जैसा है। पर उस से क्या, कैसे भी केवल चुनावी कप जीतते रहना है!

यह दूरघातक स्थिति है, जो अनेक संघ-भाजपाई भी मानते हैं। पर कहते हैंः क्या करें? यह मानसिक बदहाली इतनी व्यापक है कि किसी नीति, घोषणा, चुप्पी, बेढब स्थिति, आदि की आलोचना पर केवल यही कहते हैंः 'भाजपा के हारने से आप को क्या मिलेगा? चाहे अगले चुनाव में चार साल बाकी हो — पर उन के पास चुनाव छोड़ कोई विचार नहीं रह गया है। बारहों महीने उन्हें यही चिन्ता है। सो, अकेला लेखक भी यदि आलोचना करे तो वह चुनाव में हराने के लिए कर रहा है! अन्य कारण हो नहीं सकता।

किसी को नीति सुधार या नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं सूझती कि वह भी विचारणीय हो सकती है। जबकि वह लोकतंत्र में सब से सहज विचार है। ब्रिटेन में 2016 से 2022 के छः वर्षों में एक ही सत्ताधारी दल के चार प्रधानमंत्रियों ने स्वेच्छा से पद छोड़ दिया, सिर्फ यह देखकर कि उन की कोई नीति विफल रही या उन की लोकप्रियता कम हो गई। उन्हें पद छोड़ने की विवशता न थी! किन्तु उन्होंने अपने दल के अन्य नेता के लिए स्वयं स्थान छोड़ दिया। यह सच्ची समानता, साथीपन की भावना है। दलीय और राष्ट्रीय हित का सामंजस्य भी।

भारत में वह अकल्पनीय है! यहाँ शासक दूसरों को अपने से नीचा समझता है। आजीवन पद पर रहना अपना प्रथम अधिकार मानता है। चाहे देश का कुछ भी मत या हाल हो। यह दलीय ढाँचा भी मात्र दिखावा होने का संकेत है। मुख्य बात केवल जैसे-तैसे गद्दी पर रहने, या गद्दी लेने की है। देश की चिन्ता कहीं पीछे या बिलकुल नहीं।

एक अर्थ में भयावह हाल है कि नेताओं के पास अपने किसी काम, निकम्मेपन, मनमानी, संसाधनों की बर्बादी, नीतिगत पलटी मारने, और चुप्पी के लिए दिखावटी दलील भी न हो! जिस का जगजाहिर सबूत वर्तमान शासकों द्वारा मीडिया का सामना न करना है। न अपने दल में किसी मतभेद स्वर का। ऐसे दलीय सहकर्मी भी किनारे कर दिये गये हैं।

इस असाधारण दुर्बलता को छिपाने के लिए वे अनर्गल भाषणों का रेला देते रहते हैं, जहाँ कोई प्रश्नकर्ता न हो। केवल एकतरफा घटाटोप शब्दवर्षा। ताकि छिप जाए कि उन के पास अपने चित्र-विचित्र कर्मों-अकर्मों के बचाव में कहने को कुछ नहीं। सो, जुमले, तमाशे, दूसरों को अपशब्द, और दिवंगत नेताओं को कोसने से लोगों को उलझाए रख कर अपने को जमाने का उपाय किया गया है।

ऐसी प्रवृत्ति की निरंतरता राष्ट्रीय खालीपन है। जिसे भाजपा-भक्त 'टीना में बदल लेते हैंः कि विकल्प क्या है! उन के बौद्धिक भी आलोचनाओं का उत्तर मनगढ़ंत दलीलों से देते हैं। जब ऐसी दलीलें कट जाती हैं तो अंत में उन का ब्रह्मास्त्र है, विशेषतः हिन्दू आलोचक को — 'भाजपा के हारने से क्या मिलेगा?

यह एक तरह की ब्लैकमेलिंग है, कि भाजपा के हारते ही वामपंथी, इस्लामी लोग सत्ता में जुड़ेंगे! ऐसे ब्लैकमेलर समर्थकों को परवाह नहीं कि पिछले दस, बीस, तीस सालों में भाजपा की किसी सत्ता ने एक भी ऐसी हिन्दू विरोधी, वामपंथी, या इस्लाम-परस्त नीति को खत्म नहीं किया। उन में ऐसी नीतियाँ भी हैं जिसे मामूली संसदीय प्रस्ताव पास कर हटाया जा सकता है। जैसे, 'शिक्षा का अधिकार कानून में हिन्दुओं के विरुद्ध भेदभाव, जो गैर-हिन्दुओं को विशेष सुविधाएं देकर किया गया है। यही भेदभाव मंदिरों के संचालन पर राजकीय कब्जे से भी जारी है, जिस से मस्जिदें, चर्च मुक्त हैं। यह हिन्दुओं पर परोक्ष जजिया है जो भाजपा-राज में और बढ़ा। गैर-हिन्दुओं के लिए विशेष कोचिंग, अनुदान, संस्थान, आदि देकर।

जबकि इसी भेदभाव की निन्दा कर संघ-परिवार ने अपनी जमीन फैलाई थी। कितना बड़ा विश्वासघात कि सत्ता पा कर उन के शासकों ने वैसी किसी नीति को नहीं छुआ! बदले में झुनझुने, तमाशे, और नयी-नयी हाँक कर हिन्दू समर्थकों को बरगलाते रहे हैं। इतने विश्वास से कि लगे ही नहीं कि चुनाव जीतने के सिवा उन्हें कोई विशेष काम है। इसीलिए भाजपा शासकों के सभी भाषण पार्टी-भाषण होते हैं, राष्ट्रीय नहीं। फलतः उन के अनुयायी भी किसी न किसी को बुरा भला कहते रहते हैं। यही उन का 'विमर्श है।

अर्थात् वे मतिशून्य से हो चुके हैं। पार्टीबंदी की सनक ने उन से देश, समाज, और नीति का बोध छीन लिया है। वे अन्य दलों से घृणा करते हैं, मानो देश में उन का स्थान न हो! करोड़ो नागरिक गैर-भाजपा दलों को वोट देते हैं। इसे पक्के संघ-समर्थक बुराई समझते हैं। मानो, भाजपा नेता कुछ भी करें, सत्ता में इन्हीं को रहना चाहिए। यह 'राष्ट्रवाद नहीं, स्वार्थवाद है।

ऐसी मानसिकता में किसी नीति की बात निरर्थक हो जाती है। इसीलिए संघ-परिवार के वैचारिक सहयोगियों की स्थिति बेकार फर्नीचर जैसी है, जिन की अब उपयोगिता नहीं। नीतिगत मुद्दे, नैतिक दावे, आदि पुराने कपड़ों की तरह छोड़े जा चुके हैं। उन्हें जुमलों और नारों ने विस्थापित कर दिया है। छल-बलपूर्वक केवल एक मुद्दा जमा दिया गया है — सत्ता में कौन रहे? बाकी सभी बातें अप्रासंगिक बना दी गई हैं।

भाजपा के हटने पर इस्लामियों, वामपंथियों का हौआ दिखाया जाता है। जो वास्तविक भी है। किसी अन्य दल की सत्ता में उन्हें निश्चय ही स्थान मिलेगा, और वे अपने मुद्दों के प्रति विश्वासघात नहीं करते! इस अर्थ में, हिन्दू चेतना वाले वोटरों के लिए सचमुच आगे कुँआ, पीछे खाई है।

सो, बेचारे हिन्दू दोहरी चोट झेल रहे हैं — संघ-परिवार का विश्वासघात और ब्लैकमेलिंग। क्या इस से आगे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, राजा बाबू ने सब प्रबंध कर लिया है। कहीं कोई छिद्र नहीं छोड़ा। चाहे संवैधानिक संस्थाओं, रेफरियों पर धब्बा लगता रहे। लिहाजा चुनावी फुटबॉल का नेशनल कप वही जीतते रहेंगे। बाकी इंडिया बस वाचता रहेगा!

यह सब होशियारी जरूर है, किन्तु समाज को खोखला करते जाने की कीमत पर। बस कप हाथ में रहे, चाहे वास्तविक खेल केवल कागजी हो जाए।

गोरखपुर से पढ़ाई, रिटायरमेंट के बाद राजनीति में एंट्री, कौन थे स्कूटी से विधानसभा जाने वाले सपा विधायक आलम बदी

आर्यावर्त संवाददाता

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग नेताओं में शुमार विधायक आलम बदी आजमी का आज गुरुवार सुबह निधन हो गया। वह समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे और आजमगढ़ से 5 बार विधायक चुने गए। पेशे से इंजीनियर रहे बदी का गोरखपुर से काफी गहरा नाता रहा है। वह अपनी सादगी भरी जिंदगी के लिए जाने जाते रहे हैं। हालांकि उनकी राजनीति में एंट्री देरी से हुई लेकिन वह जल्द ही सियासी गलियारे में असरदार नेता की छवि बनाने में कामयाब रहे।

आलम बदी प्रदेश के सबसे उम्रदराज विधायक थे। वह आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा सीट से विधायक चुने जाते रहे। उनकी राजनीति में एंट्री काफी देरी से हुई। सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद वह राजनीति में आए और

निजामाबाद से लड़े और जीत गए

मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। देरी से आने के बाद भी उनकी शुरुआत बेहद शानदार रही और पहले ही प्रयास में विधायक चुन लिए गए।

60 साल की उम्र में सियासी समर में कूदने वाले बदी को मुलायम सिंह ने 1996 के विधानसभा चुनाव में निजामाबाद सीट से मैदान में उतारा और उन्होंने कड़े मुकाबले में अपनी पहली बाधा पार की। 2002 के चुनाव में भी उन्हें कामयाबी हासिल हुई। हालांकि 2007 के चुनाव में यूपी में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी जीत हासिल कर सत्ता पर कब्जा जमाया था। पार्टी की शानदार जीत में निजामाबाद सीट भी शामिल रही। इस चुनाव में निजामाबाद से बदी को बीएसपी के अंगद यादव के हाथों हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस हार के बाद बदी ने इसी सीट से अपनी जीत की हैट्रिक भी पूरी की। उन्होंने 2012, 2017 और 2022 के चुनाव में जीत हासिल की।

गोरखपुर के इस्लामिया से पूरी की पढ़ाई

बदी का जन्म 16 मार्च 1936 को आजमगढ़ में हुआ था। लेकिन उनकी स्कूली शिक्षा गोरखपुर में हुई। गोरखपुर के बक्शीपुर स्थित इस्लामिया इंटर कॉलेज में उनके पिता वदीउज्जमा आजमी गेम टीचर हुआ करते थे। ऐसे वह भी यहीं पर रहे और इसी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। फिर उन्होंने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा की डिग्री हासिल की। उनकी नौकरी सिंचाई विभाग में लगी। उन्होंने गोरखपुर की गोला तहसील के साथ-साथ कई जगहों पर काम किया। नौकरी से रिटायर होने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा।

76 साल बाद सर्टिफिकेट लेने आए

उन्होंने 1950 में इस्लामिया से हाईस्कूल की परीक्षा पास की थी। लेकिन तब वह किन्हीं वजहों से सर्टिफिकेट नहीं ले सके थे। इसके 76 साल बाद इस साल अप्रैल में स्कूल गए जहां भव्य कार्यक्रम में उनके यह सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। अपनी ईमानदारी और सादगी को लेकर सियासी गलियारों में खास पहचान रखने वाले बदी को कई बार मंत्री बनने का ऑफर तक दिया गया। लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि उनकी जगह किसी युवा को यह जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव से भी उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं।

रोडवेज बस और स्कूटी से सफर

सरकारी नौकरी, फिर राजनीति और वह भी 5 बार की विधायकी। लेकिन आलम बदी बेहद साधारण जिंदगी जीते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वह विधायक बनने के बाद भी महंगी और बड़ी गाड़ियों में सफर करने की जगह रोडवेज बसों में सफर किया करते थे। लखनऊ में विधानसभा जाने के लिए वह अपनी स्कूटी का इस्तेमाल करते थे। वह वीआईपी कल्चर यानी गनर या किसी तरह की सुरक्षा नहीं लेते थे।

2 से 3 लाख में चुनाव जीतने वाले

90 साल की उम्र में चुनाव जीतने वाले बदी की ईमानदार और सादगी भरी छवि उनके कई प्रतिद्वंद्वियों पर भारी पड़ती थी। वह कभी भी बड़े काफिले के साथ चुनाव प्रचार करने नहीं गए। ऐसे समय में जब चुनाव जीतने के लिए नेता लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करते हैं तब भी बदी एक चुनाव में महज 2 से 3 लाख रुपये भी खर्च किया करते थे। उन्हें जीत भी मिलती थी। 5 बार विधायक होने के बाद भी उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं रही। उनके पास करीब चल-अचल मिलाकर करीब 40 लाख रुपये की संपत्ति रही। साथ में उनके नाम से एक कार भी रही।

शिक्षक पर शराब का सेवन सही पाया गया

जौनपुर। सिरकोनी ब्लॉक क्षेत्र के बीबीपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय पर कार्यरत एक शिक्षक पर शराब का सेवन कर विद्यालय आने और बच्चियों के साथ बैड टच किये जाने का गंभीर आरोप लगा है। जिसकी जांच गुरुवार को खंड शिक्षा अधिकारी ने किया।उन्होंने अपनी जांच में शिक्षक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु अपनी रिपोर्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपी है। सिरकोनी ब्लॉक के बीबीपुर कंपोजिट विद्यालय विद्यालय पर कार्यरत सहायक अध्यापक प्रदीप कुमार सिंह पर ग्राम प्रधान वीरेंद्र सिंह चैहान ने आरोप लगाया कि स्कूल के बच्चियां व उनके अभिभावक बार बार उक्त अध्यापक पर शराब पीकर आने तथा छात्राओं को बैड टच करने का आरोप लगा रहे थे।शिक्षक प्रदीप सिंह की आए दिन शिकायत हो रही थी।सहायक अध्यापक प्रदीप कुमार सिंह द्वारा शराब पीकर बेड टच करने से विद्यालय की पढ़ने वाली बच्चियों अपने आप को असहज महसूस करती हैं।

पोस्टर में सानिया मौर्य, काव्य लेखन में हिमांशी प्रथम

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर।। दीक्षोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेंगड़ी विधि संस्थान द्वारा मेरी माँ विषय पर पोस्टर एवं काव्य लेखन प्रतियोगिता का आयोजन एस.पी. गुप्ता मेमोरियल लाइब्रेरी में हुआ।प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों एवं विभागों के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लेते हुए अपनी रचनात्मक प्रतिभा, कलात्मक अभिव्यक्ति एवं साहित्यिक संवेदनशीलता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों ने अपने पोस्टरों और कविताओं के माध्यम से विकसित भारत के सपनों, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका तथा माँ के प्रति सम्मान, प्रेम और समर्पण की भावनाओं को सशक्त अभिव्यक्ति दी।पोस्टर प्रतियोगिता का मूल्यांकन डॉ. वनिता सिंह, डॉ. प्रियंका कुमारी, डॉ. शुभम सिंह एवं डॉ. आश्रेया दुबे

ने किया। प्रतियोगिता में सानिया मौर्य ने प्रथम, आशीष शैलेंद्र प्रजापति ने द्वितीय तथा खुशी सिंह एवं अंकुर मौर्य ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया।काव्य लेखन प्रतियोगिता का मूल्यांकन डॉ. इंद्रजीत सिंह एवं डॉ. दिनेश कुमार सिंह ने किया। इसमें हिमांशी श्रीवास्तव ने प्रथम, अनुराग यादव ने द्वितीय तथा शशिकांत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। समन्वयक डॉ. अनुराग मिश्र ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ विद्यार्थियों में सृजनात्मक चिंतन, साहित्यिक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती हैं।

महिला अस्पताल में डीएम का निरीक्षण

जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने गुरुवार को जिला महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों, दवा वितरण कक्ष, वार्डों तथा अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया।जिलाधिकारी ने अस्पताल में उपलब्ध दवाओं, मरीजों को दी जा रही सुविधाओं तथा कर्मचारियों की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर की साफ-सफाई, मरीजों की सुविधा तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया। डीएम ने अस्पताल में मौजूद मरीजों एवं उनके परिजनों से भी बातचीत कर उपचार और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मरीजों को समय पर और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।

घर-घर पहुंचाएंगे डायरिया से बचाव के संदेश

सीएमओ ने प्रचार वाहनों को दिखाई हरी झंडी

आर्यावर्त संवाददाता

फर्रुखाबाद। डायरिया के प्रति जन जागरूकता के लिए गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से तीन प्रचार वाहनों को रवाना किया। यह प्रचार वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर शून्य से पांच साल तक के बच्चों में डायरिया के लक्षण, कारण और बचाव आदि के बारे में प्रचार-प्रसार करेंगे।

इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि शून्य से पांच साल तक के बच्चों को डायरिया से सुरक्षित बनाने के लिए जन जागरूकता बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए डायरिया के प्रति जागरूकता सम्बन्धी संदेशों वाले पोस्टर-बैनर से सुसज्जित यह प्रचार वाहन जन-जन तक डायरिया से डरने नहीं बल्कि सतर्क रहने का सन्देश पहुंचाएंगे। मुख्य चिकित्सा

अधिकारी ने कहा कि जिले में इस समय डायरिया रोको अभियान चलाया जा रहा है। डायरिया रोको अभियान में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू भी "डायरिया से डर नहीं" कार्यक्रम के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। अभियान का उद्देश्य बच्चों में डायरिया की रोकथाम, ओआरएस व जिंक के उपयोग को प्रोत्साहन और समुदाय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है।

जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. सर्वेश यादव ने कहा कि बारिश और उमस में बच्चे डायरिया की चपेट में कई कारणों से आ सकते हैं, जैसे- दूषित जल पीने से, दूषित हाथों से भोजन बनाने या बच्चे को खाना खिलाने, खुले में शौच करने या बच्चों के मल का ठीक से निस्तारण न करने आदि से। इसलिए शौच और बच्चों का मल साफ़ करने के बाद, भोजन बनाने और खिलाने से पहले हाथों को साबुन-पानी से अच्छी तरह अवश्य धुलें। डायरिया का सही इलाज ओआरएस का घोल और जिंक के टेबलेट हैं, जिन्हें उम्र के अनुसार निश्चित अवधि तक जरूर दें। उन्होंने कहा कि बच्चे को दिन भर में तीन या तीन से अधिक बार पतली दस्त हो तो समझना चाहिए कि बच्चा डायरिया से ग्रसित है और ऐसे में उसको तत्काल ओआरएस का घोल देना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न होने पाए, साथ ही निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करना चाहिए।

इस मौके पर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर. सी. माथुर, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक कंचन बाला, डीसीपीएम रणविजय प्रताप सिंह, पी.एस.आई. इंडिया से अमरीश पाण्डे, अनुपम मिश्र और अन्य सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

नगरी क्षेत्रों में एंटीलार्वा रसायन का छिड़काव करायें

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में संचारी दस्तक अभियान संबंधित अंतर्विभागीय समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। जिलाधिकारी ने अभियान संबंधित समस्त गतिविधियों को निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार संपादित करने के निर्देश दिए। पंचायती राज विभाग को समस्त ग्राम पंचायतों में झाड़ियों की कटाई, जल निकासी, साफ-सफाई के निर्देश दिए एवं समस्त स्कूलों, कॉलेज में नियमित फॉगिंग, एंटीलार्वा रसायन का छिड़काव कराने के निर्देश दिए। समस्त अधिशासी अधिकारियों को नगरीय क्षेत्रों के समस्त वार्डों, मोहल्लों एवं स्कूलों में सघन रूप से साफ-सफाई, फॉगिंग, एंटीलार्वा रसायन का छिड़काव कराए जाने के निर्देश दिए। पशुपालन विभाग को निर्देशित किया कि समस्त शूकर पालकों की साफ-सफाई, कीटनाशी रसायन स्प्रे, शूकर को खुले में न छोड़ने हेतु सेंस्टाइज करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के समस्त अधीक्षक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये कि वे अपने ब्लॉक में शत-प्रतिशत आशा भ्रमण, लक्षण युक्त मरीजों को चिन्हीकरण, संचारी रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करने, समस्त दवाओं, किट्स, प्लेटलेट्स की उपलब्धता आदि सुनिश्चित करें। समस्त गतिविधियों की व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। डेंगू एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों पर नियंत्रण हेतु समस्त तैयारियां सुनिश्चित करें। समस्त स्कूलों कॉलेज में साफ-सफाई, झाड़ी कटाई, छात्र छात्राओं को संक्रामक रोगों से बचाव हेतु जागरूक करने, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने की व्यवस्था किए जाने हेतु निर्देशित किए। मुख्य विकास अधिकारी सहित समस्त विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहें।

पहली ही बारिश में धंसा गंगा एक्सप्रेसवे... हरदोई में 10 मीटर सड़क नीचे बैठी, उखड़ी गिट्टियां, UPEIDA ने बैठाई जांच

आर्यावर्त संवाददाता

हरदोई। उत्तर प्रदेश के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे की मजबूती को लेकर पहली ही तेज बारिश में बड़ा झटका लगा है। राज्य के हरदोई जिले के पास एक्सप्रेसवे का लगभग 10 मीटर लंबा हिस्सा अचानक धंस गया। इस घटना ने न केवल निर्माण एजेंसी के दावों की पोल खोल दी है, बल्कि पूरे प्रोजेक्ट की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। घटना की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) के वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियरों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।

शुरुआती पड़ताल के अनुसार, इलाके में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सड़क के निचले हिस्से की मिट्टी कमजोर होकर

खिसक गई, जिससे ऊपरी डामर/कंक्रीट की परत धंस गई। गनीमत यह रही कि इस घटना के दौरान कोई वाहन क्षतिग्रस्त हिस्से की चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। अधिकारियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए प्रभावित क्षेत्र के आसपास बैरिकेडिंग कर दी है और वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह रोक लगाकर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की है। मामला हाइलाइट होते ही निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारियों में हड़कंप मच गया। घटना के तुरंत बाद संबंधित निर्माण एजेंसी और तकनीकी विशेषज्ञों को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। विशेषज्ञ अब इस बात की बारीक जांच कर रहे हैं कि सड़क के धंसने की वजह सिर्फ प्राकृतिक आपदा (अत्यधिक बारिश) है या फिर इसके निर्माण में घटिया सामग्री और तकनीकी लापरवाही जिम्मेदार रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वाले ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विपक्ष को मिला मुद्दा, सरकार के सामने गुणवत्ता सिद्ध करने की चुनौती

गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को मजबूत करने वाली सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल है। एक्सप्रेसवे के शुरुआती चरण में ही सड़क धंसने की घटना के बाद विपक्षी दलों को राज्य सरकार पर हमला बोलने का बड़ा मुद्दा मिल गया है। आगामी समय में एक्सप्रेसवे को जनता के लिए पूरी तरह सुरक्षित और चालू रखने के लिए सरकार व निर्माण एजेंसियों के सामने अपनी साख बचाने तथा निर्माण की मजबूती का भरोसा दिलाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।

कांवड़ रखने के लिए सम्मानजनक व्यवस्था करें : डीएम

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। आगामी श्रावण मास, कांवड़ यात्रा, नागपंचमी एवं चेहलुम को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा मुख्यमंत्री द्वारा इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय स्थापित करते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि त्रिलोचन महादेव, गौरीशंकर धाम, चैकिया धाम सहित अन्य प्रमुख मंदिरों पर सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी की जाएगी तथा कंट्रोल रूम संचालित रहेंगे। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रवेश एवं निकास के पृथक मार्ग निर्धारित किए जाएंगे तथा महिला पुलिस बल सहित पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी। कांवड़ मार्गों एवं प्रमुख मेलों के लिए कुछ प्रभावी ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू रहेगा। मानसून के दृष्टिगत स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय में एंटी-स्नेक वेनम की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। कांवड़ मार्गों पर प्रमुख स्थानों पर हेल्थ बूथ स्थापित किए जाएंगे, जहां चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, ओआरएस एवं आवश्यक दवाएं उपलब्ध रहेंगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नगर पालिका एवं जिला पंचायत राज विभाग को निर्देशित किया गया कि मंदिर परिसरों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक स्थलों पर कांवड़ रखने हेतु सम्मानजनक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए धरना, आजम के समर्थन में आज रामपुर पहुंच रहा सपा डेलीगेशन

आर्यावर्त संवाददाता

रामपुर। उत्तर प्रदेश में जौहर यूनिवर्सिटी पर सियासी बवाल जारी है। सपा का 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज रामपुर जाएगा। इस नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय करेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोकने की मांग करेंगे। इसके लिए धरना देंगे। जिलाधिकारी रामपुर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में वर्तमान विधायक के साथ-साथ पूर्व विधायक भी शामिल हैं। बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2006 में हुई थी और इसके संस्थापक समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान हैं।

जिला प्रशासन रामपुर द्वारा इस पर बुलडोजर एक्शन की कार्यवाही की जा रही है। इसको लेकर सपा नेता नाराज हैं और आजम खान को सपोर्ट करने के लिए रामपुर जा रहे हैं। सपा का कहना है कि यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाना शैक्षिक ढांचे और 'शिक्षा के अधिकार' को ध्वस्त करने जैसा है। यह संवैधानिक भावना के विपरित है। प्रशासन और सरकार का यह कदम समाज के गरीब, पिछड़े और दलित वर्गों को शिक्षा से वंचित करने जैसा है। यहां से नाम मात्र की फीस पर सभी धर्मों के लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें गिराने का आदेश

रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इन 38 इमारतों को बनाने से पहले सरकारी नियम के मुताबिक नक्शा पास नहीं कराया गया था। यह फैसला 'उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973' के तहत लिया गया है। इसके मुताबिक बिना मंजूरी के बने निर्माण अवैध माने जाते हैं। आदेश जारी करने से पहले प्रशासन ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को नोटिस भेजकर उनका पक्ष जानना चाहा था।

वहीं, यूनिवर्सिटी का कहना है कि इमारतें पहले ही बन चुकी थीं, इसलिए मौजूदा नियमों के तहत उन्हें अवैध नहीं ठहराया जा सकता। उस समय यह RDA के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, इसलिए उससे भवन निर्माण की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं थी। हालांकि, प्राधिकरण ने कहा कि निर्माण के समय जिस सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेना जरूरी था, उसकी अनुमति अनिवार्य थी।

डेंगू पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अब तक 5 संक्रमित

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। जिले में डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सक्रिय है। गुरुवार को लाइन बाजार मोहल्ले में डेंगू मरीज मिलने के बाद जिला मलेरिया अधिकारी सुनील कुमार यादव के नेतृत्व में टीम ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान फीवर सर्वे, डेंगू जांच, मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान, जलभराव वाले स्थानों पर एंटी-लार्वा रसायन का छिड़काव, पोस्टर चस्पा करने, पंपलेट वितरण और लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया गया।स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जनवरी से अब तक जनपद में डेंगू के कुल 5 मरीज मिल चुके हैं। विभाग ने बताया कि डेंगू मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, जो साफ पानी में पनपता है और सुबह-शाम अधिक सक्रिय रहता है। तेज बुखार, शरीर व जोड़ों में दर्द, उल्टी, प्लेटलेट्स में कमी और रक्तस्राव जैसे

लक्षण दिखाई देने पर तुरंत सरकारी अस्पताल में जांच कराने की सलाह दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गंगाराम गौतम ने लोगों से अपील की है कि डेंगू के लक्षण दिखने पर लापरवाही न करें और स्वयं दवा लेने या झोलाछाप चिकित्सकों से इलाज कराने से बचें। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डेंगू की जांच, उपचार, दवाएं, प्लेटलेट्स और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। जिला मलेरिया अधिकारी सुनील कुमार यादव ने नागरिकों से घरों के आसपास साफ-सफाई रखने, पानी जमा न होने देने, कूलर व गमलों का पानी सप्ताह में एक बार बदलने, पूरी बांह के कपड़े पहनने और मच्छरदानी व जालियों का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ष्हर रविवार मच्छर पर वार, लार्वा पर प्रहारष् अभियान के तहत प्रत्येक सप्ताह घर और आसपास जमा पानी को अवश्य हटाएं, ताकि डेंगू जैसी मच्छरजनित बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

दिमाग के लिए जरूरी होता है विटामिन बी12?

हर साल 22 जुलाई का दिन वर्ल्ड ब्रेन डे के रूप में जाना जाता है। ये मौका लोगों को दिमाग की हेल्थ के प्रति जागरूक करने का है। जानें दिमाग के लिए विटामिन बी12 कितना जरूरी होता है? ये कैसे काम करता है और शरीर में इसकी कमी होने पर क्या होता है।

दिमाग हमारे शरीर का मदरबोर्ड है और अगर ये ही कमजोर महसूस करने लगे तो चिंता करना बहुत जरूरी है। आज लोग स्ट्रेस में रहते हैं लेकिन उन्हें इसका पता ही नहीं चलता है। चीजों को भूल जाना, हर समय स्ट्रेस, ध्यान न लगा पाना और ऐसी कई दिक्कतें होती हैं जो दिमाग के बिगड़े हुए स्वास्थ्य को दर्शाती हैं। दिमाग की हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। इसी मौके पर हम आपको दिमाग और विटामिन बी12 के बीच क्या कनेक्शन है ये एक्सपर्ट के जरिए बताने जा रहे हैं।

कहीं आपको भी तो हर समय थकान नहीं रहती है? ये विटामिन बी12 की कमी का संकेत है और ये थकान हमारे दिमाग की सेहत को भी प्रभावित करती है। वर्ल्ड ब्रेन डे के मौके पर जानें दिमाग के लिए विटामिन बी12 क्यों बेहद जरूरी है।

22 जुलाई को मनाए जाने वाले वर्ल्ड ब्रेन डे का उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि दिमाग की सेहत कितनी जरूरी है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की रोकथाम, इनकी समय पर पहचान और बेहतर इलाज के बारे में लोगों को बताया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी (World Federation of Neurology) ने इसकी साल 2014 में शुरुआत की। इस मौके पर दुनियाभर के एक्सपर्ट, हेल्थ इंस्टीट्यूट और संगठन ब्रेन हेल्थ से जुड़ी जानकारियां लोगों से शेयर करते हैं। साथ ही वो लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए भी प्रेरित करते हैं।

दिमाग के लिए क्यों जरूरी है विटामिन बी12

डॉ. लक्ष्मण रामचंद्रन (कंसल्टेंट फिजिशियन) कहते हैं कि जब भी हम ब्रेन हेल्थ की बात करते हैं, तो सबसे पहले नींद, एक्सरसाइज या फिर दिमाग को एक्टिव रखने वाली चीजें याद आती हैं। लेकिन एक विटामिन बी12 एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। यह हमारे दिमाग और पूरे नर्वस सिस्टम को सही तरीके से काम करने में बहुत अहम रोल निभाता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए, तो सबसे पहले असर दिमाग और नसों पर दिख सकता है।

कैसे काम करता है विटामिन बी12

यह हमारी नसों के ऊपर मौजूद एक प्रोटेक्टिव लेयर को हेल्दी रखने में मदद करता है, जिसे Myelin Sheath कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर लगी कवरिंग। यही कवरिंग दिमाग से शरीर तक और शरीर से दिमाग तक जाने वाले मैसेज को सही और तेज तरीके से पहुंचाने में मदद करती है। इसलिए, जब विटामिन बी12 की कमी हो जाती है, तो ये मैसेज ठीक से नहीं पहुंच पाते और दिमाग की फंक्शनिंग पर असर पड़ सकता है।

इसके अलावा विटामिन बी12 डीएनए बनाने और हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनने में भी मदद करता है। ये रेड ब्लड सेल्स शरीर के हर हिस्से, खासकर दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। इसलिए शरीर में विटामिन बी12 का सही लेवल बना रहना, ब्रेन के नॉर्मल काम करने के लिए भी जरूरी है।

विटामिन बी12 की कमी के लक्षण

विटामिन बी12 की कमी की एक बात यह है कि इसके लक्षण धीरे धीरे सामने आते हैं। शुरुआत में कई लोगों को बार बार चीजें भूलना, ध्यान लगाने में परेशानी होना, कन्फ्यूजन महसूस होना या मूड में बदलाव जैसे लक्षण दिख सकते हैं। कुछ लोगों को हाथों और पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन भी महसूस हो सकता है।

रिसर्च बताती है कि विटामिन बी12 की कमी का संबंध कई तरह की न्यूरोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों से देखा गया है।

किन लोगों में है ज्यादा खतरा

कुछ लोगों में विटामिन बी12 की कमी होने का खतरा ज्यादा होता है। जैसे बढ़ती उम्र के लोग, जो लोग पूरी तरह Vegan डाइट फॉलो करते हैं, या फिर जिन्हें ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें शरीर विटामिन बी12 को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अच्छी बात यह है कि विटामिन बी12 की कमी का पता ब्लड टेस्ट से लगाया जा सकता है और जरूरत के हिसाब से डाइट, सप्लीमेंट्स या इंजेक्शन से इसका इलाज किया जा सकता है।

इसलिए अगर आपको लंबे समय से भूलने की समस्या, ध्यान लगाने में दिक्कत या हाथ पैरों में झुनझुनी जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो इन्हें नजरअंदाज न करें। समय पर जांच और इलाज आपके दिमाग और नसों दोनों को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है।

महिलाओं में ट्यूब ब्लॉक होना खतरनाक, इसका कैसे पता चलता है

प्रेगनेंसी कंसीव करने में अगर दिक्कत आ रही हो तो इसमें एक जांच फैलोपियन ट्यूब की भी की जाती है। ये महिलाओं में प्रजनन तंत्र का अहम हिस्सा है क्योंकि ये एग को गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करती हैं। कुछ कारणों की वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और प्रेगनेंट होने में प्रॉब्लम आने लगती है। एक्सपर्ट बताते हैं कि पेल्विक इंफेक्शन, एंडोमेट्रियोसिस, यौन संक्रमण के कारण ऐसा हो सकता है। कभी-कभी टीबी जैसी बीमारियों की वजह से भी ऐसा होता है।

शुरुआत में इसके लक्षण नजर नहीं आते हैं। जब लंबे समय तक प्रेगनेंट होने में प्रॉब्लम आती है तब इसका पता चलता है। इस आर्टिकल में आयुर्वेद एक्सपर्ट से जानें महिलाओं में ट्यूब का ब्लॉक होना कितना खतरनाक है? इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए और किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए।

आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर चंचल शर्मा कहती हैं वो सिर्फ कुछ समय के इलाज के बजाय पूरी तरह से और नेचुरली ठीक होने में विश्वास रखती हैं। बांझपन के इलाज के लिए आयुर्वेद सबसे अच्छा काम करता है क्योंकि इसमें ऐसी कोई भारी दवा नहीं दी जाती जिसके साइड-इफेक्ट्स हों।

एचएसजी टेस्ट कराना है जरूरी

एचएसजी या हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राम एक खास तरह का एक्सरे है जो गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब की जांच करता है ताकि यह पक्का हो सके कि वे ठीक से काम कर रहे हैं।

ट्यूब ब्लॉकेज के नेचुरल इलाज के आयुर्वेदिक उपचार:

लाइफस्टाइल और दिनचर्या: डॉक्टर चंचल कहती हैं कि अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अगर आप सच में नेचुरली कंसीव करना चाहती हैं तो आपको सही तरीके से बनी दिनचर्या का पालन करना होगा।

एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट: एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों और एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन C से भरपूर हल्दी, अदरक, लहसुन और खट्टे फल खाएं।

अनहेल्दी आदतों को छोड़ना: स्मोकिंग और शराब से बचें क्योंकि ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फैलोपियन ट्यूब के काम पर बुरा असर डाल सकते हैं।

योग/मेडिटेशन: तनाव हार्मोनल असंतुलन का एक बड़ा कारण है। रोजाना 5-10 मिनट मेडिटेशन करने से तनाव कम हो सकता है। कुछ खास योगासन पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।

पेल्विक/पेट की मालिश: कुछ स्पेशलिस्ट ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने और पेल्विक एडहेसन्स को कम करने के लिए पेट की मालिश करने की सलाह देते हैं।

आयुर्वेदिक दवा: कुछ पारंपरिक तरीके, जैसे कि 'उत्तर बस्ती' (एक ऐसी तकनीक जिसमें दवा वाले तेल को धीरे-धीरे गर्भाशय में डाला जाता है), का मकसद ट्यूब में आई रुकावटों (ट्यूब-अडेशन्स) को खत्म करना होता है।

10 में 9 भारतीयों को हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा, आईसीएमआर की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

अगर आपका वजन सामान्य है, तब भी हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा हो सकता है। आईसीएमआर की रिपोर्ट बताती है कि असामान्य कोलेस्ट्रॉल अब बड़ी संख्या में भारतीयों को प्रभावित कर रहा है।

अगर आपको लगता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल सिर्फ मोटापे या बढ़ती उम्र की समस्या है, तो यह खबर आपको चौंका सकती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की एक नई रिपोर्ट बताती है कि देश के लगभग 87% वयस्क किसी न किसी तरह की असामान्य कोलेस्ट्रॉल (डिस्लिपिडिमिया) की समस्या से जूझ रहे हैं। यानी हर 10 में से करीब 9 लोगों के शरीर में अच्छे और बुरे कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ा हुआ है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होती, क्योंकि शुरुआती दौर में इसके कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते।

आईसीएमआर-INDIAB अध्ययन के मुताबिक, महिलाओं, शहरों में रहने वाले लोगों और मध्य भारत के लोगों में यह समस्या अपेक्षाकृत ज्यादा देखी गई है। इसके अलावा डायबिटीज, प्री-डायबिटीज, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहने से दिल की धमनियों में चर्बी जमा होने लगती है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

वजन से नहीं लगता अंदाजा

रिपोर्ट में बताया गया है कि डिस्लिपिडिमिया का मतलब सिर्फ खराब (LDL) कोलेस्ट्रॉल बढ़ना नहीं है। कई लोगों में अच्छा (HDL) कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जबकि कुछ में ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर ज्यादा पाया जाता है। ये सभी स्थितियां दिल की बीमारियों के जोखिम को बढ़ाती हैं। चिंता की बात यह है कि देखने में पूरी तरह स्वस्थ और सामान्य वजन वाले लोगों में भी यह समस्या हो सकती है। इसलिए केवल वजन देखकर यह मान लेना कि कोलेस्ट्रॉल सामान्य होगा, सही नहीं है।

किन चीजों से रहना चाहिए दूर

विशेषज्ञों का कहना है कि 30 वर्ष की उम्र के बाद नियमित लिपिड प्रोफाइल जांच करानी चाहिए, खासकर अगर परिवार में हृदय रोग, डायबिटीज या हाई बीपी का इतिहास रहा हो। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, तली-भुनी और प्रोसेस्ड चीजों से दूरी, धूम्रपान और शराब से बचाव तथा पर्याप्त नींद जैसी आदतें कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद करती हैं। समय रहते जांच और जीवनशैली में बदलाव करके दिल की कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है।

किस उम्र के लोगों में खतरा ज्यादा

अध्ययन में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 23,665 लोगों की लिपिड प्रोफाइल का विश्लेषण किया गया। अध्ययन से पता चला कि 30 से 39 वर्ष के लोगों में डिस्लिपिडिमिया यानी असामान्य कोलेस्ट्रॉल का खतरा सबसे ज्यादा है और इसकी शुरुआत अक्सर 30 साल की उम्र के आसपास ही हो जाती है। डायबिटीज विशेषज्ञ डॉ आर एम अंजना के मुताबिक, अब असामान्य कोलेस्ट्रॉल ज्यादातर भारतीय वयस्कों में आम समस्या बन चुका है।

शहरी महिलाओं में ज्यादा जोखिम

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि शहरी महिलाओं में यह जोखिम गांव की महिलाओं की तुलना में ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रोसेस्ड फूड, लंबे समय तक बैठे रहकर काम करना और शारीरिक गतिविधियों की कमी इसकी बड़ी वजह हैं। उनका मानना है कि सिर्फ डायबिटीज, मोटापा या हाई बीपी वाले लोगों की ही नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर नियमित कोलेस्ट्रॉल जांच और समय रहते जीवनशैली में बदलाव की जरूरत है, ताकि भविष्य में हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे गंभीर खतरे को कम किया जा सके।

हार्ट अटैक के लक्षण

2025 की आईसीएमआर और एम्स के एक अध्ययन में युवाओं की अचानक मौतों का सबसे बड़ा कारण दिल से जुड़ी बीमारियां बताई गई हैं। दिल की मौतों में 85% मामलों में धमनियों में चर्बी जमने (कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़) से हार्ट अटैक होना सबसे प्रमुख वजह बताई गई है।

गुड कोलेस्ट्रॉल की भारी कमी

जर्नल ऑफ क्लिनिकल लिपिडोलॉजी में पब्लिश हुई इस स्टडी में 23,665 लोगों के डेटा का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि 66.8% वयस्कों में गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम था, जो खून से फैट को साफ करने में मदद करता है। वहीं 49.4% वयस्कों में बैड कोलेस्ट्रॉल और 29.5% वयस्कों में ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया। इस स्टडी में यह पता चला कि जैसे ही व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स बिगड़ता है, यह समस्या और तेजी से बढ़ती है।

डॉक्टर तरुण कुमार कहते हैं, 'भारत में अब हार्ट अटैक के मामले युवाओं में भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 50 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक आम हो गया है। कुल मामलों में 25-30% केस 40 साल से कम उम्र के युवाओं के होते हैं।'

5 साल पुरानी कंपनी का धमाका, शेयर बाजार में लिस्ट होते ही पैसा किया डबल

मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज ने मंगलवार को को शेयर बाजार में ज़बरदस्त शुरुआत की। इसके शेयर BSE SME प्लेटफॉर्म पर 628।90 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुए, जो 331 रुपये के इश्यू प्राइस से 90 प्रतिशत ज्यादा है। जबकि कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी के शेयर 660।30 रुपए पर पहुंच गए, जोकि इश्यू प्राइस से करीब 100 फीसदी ज्यादा हैं।

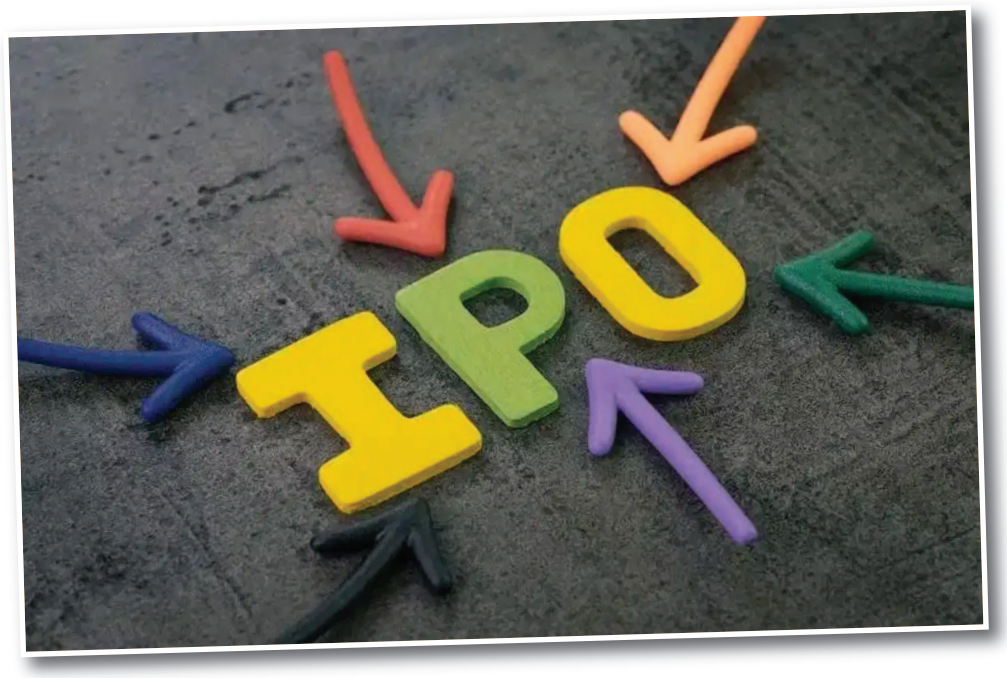

काफी कम कंपनियां ही ऐसा कारनामा करने में कामयाब होती है, जो मंगलवार के दिन शेयर बाजार में एसएमई कंपनी ने अपनी लिस्टिंग के दिन कर दिखाया। कंपनी ने कारोबारी सत्र के दौरान निवेशकों का पैसा डबल कर दिया। इस कंपनी का नाम है मिलवर्क्स टेक्नोलॉजी। जिसकी शुरुआत करीब 5 साल पहले हुई थी। मंगलवार के दिन शेयर बाजार में कंपनी का डेब्यू काफी धमाकेदार देखने को मिला। इश्यू प्राइस से कारब 90 फीसदी के प्रीमियम के साथ लिस्ट होने के बाद इश्यू प्राइस के मुकाबले शेयर के दाम करीब 100 फीसदी तक बढ़ गए। इसका मतलब है कि निवेशकों का पैसा पूरी तरह से डबल हो गया। आइए इसे जरा आंकड़ों की जुबानी समझने की कोशिश करते हैं।

कंपनी की धमाकेदार शुरुआत

मिलवर्क्स टेक्नोलॉजी ने मंगलवार, 21 जुलाई को शेयर बाज़ार में जबरदस्त शुरुआत की। इसके शेयर BSE SME प्लेटफ़ॉर्म पर 628।90 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुए, जो 331 रुपए के इश्यू प्राइस से 90 प्रतिशत ज्यादा है। मौजूदा समय में कंपनी के शेयर में करीब 100 फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है कंपनी का शेयर 660।30 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। यह शानदार लिस्टिंग कंपनी के इनिशियल पब्लिक ऑफ़रिंग (IPO) को मिले ज़बरदस्त रिस्पॉन्स के बाद हुई है, जिसे 14 जुलाई से 16 जुलाई तक चली बिडिंग के दौरान 193।14 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

जबरदस्त मिला था रिस्पांस

160।34 करोड़ रुपए के इस इश्यू में ऑफर किए गए 35,18,800 शेयरों के मुकाबले 67,96,30,000 शेयरों के लिए भारी बिड मिलीं। इस मांग में रिटेल इन्वेस्टर्स की अहम भूमिका रही, जिन्होंने अपने लिए रिज़र्व हिस्से को 216।46 गुना सब्सक्राइब किया। नॉन-इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी ने भी काफ़ी दिलचस्पी दिखाई और उनका कोटा 194।05 गुना बुक हुआ। इस IPO में 48।44 लाख इक्विटी शेयरों का नया इश्यू शामिल था और इसमें 'ऑफर-फॉर-सेल' का कोई हिस्सा नहीं था। इसकी कीमत 315 रुपए से 331 रुपए प्रति शेयर के दायरे में तय की गई थी। लॉट साइज 400 शेयर तय किया गया था, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को कम से कम दो लॉट (800 शेयर) के लिए अप्लाई करना था, जिसके लिए ऊपरी प्राइस बैंड पर 2,64,800 रुपए का इन्वेस्टमेंट जरूरी था।

ऐसे किया पैसा डबल

जैसा कि हमने आपको बताया कि इश्यू में दो लॉट में निवेश करना जरूरी था। इसका मतलब है कि 800 शेयरों को खरीदना था। एक शेयर की कीमत 331 रुपए थी। इसका मतलब है कि 800 शेयरों की कीमत 2,64,800 रुपए थी। कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी का शेयर 660।30 रुपए पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि 800 शेयरों की वैल्यू 5,03,120 रुपए हो गई। इसका मतलब है कि निवेशकों को 2,38,320 रुपए का प्रॉफिट हुआ।

कहां पैसा खर्च करेगी कंपनी

लिस्टिंग से पहले, Millworks Technologies को लेकर बाजार का मूड काफी पॉजिटिव था। Investorgain और IPO Watch के अनुसार, ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) लगभग 395 रुपए प्रति शेयर था, जिससे इश्यू प्राइस पर लगभग 120 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन का संकेत मिल रहा था। हालांकि, SME IPO से होने वाले गेन की सीमा 90 प्रतिशत तय है। एंकर इन्वेस्टर की बिडिंग 13 जुलाई को पूरी हुई, जिसमें कंपनी ने नौ एंटिटीज से लगभग 44 करोड़ रुपए जुटाए थे। जिनमें राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज और एवरग्रो कैपिटल अपॉर्चुनिटीज़ फंड शामिल हैं। कंपनी नए इश्यू से मिली नेट रकम का इस्तेमाल विस्तार और ऑपरेशनल जरूरतों के लिए करने की योजना बना रही है। इसमें से 61।03 करोड़ प्लांट और मशीनरी खरीदने के लिए, 81।50 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल की जरूरतों के लिए और बाकी रकम सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए तय की गई है।

अब बिना इंटरनेट के भी धड़ाधड़ होगा यूपीआई पेमेंट, आ रहा है ये धांसू फीचर, जानकर खुशी से झूम उठेंगे आप

आम लोगों के लिए यूपीआई से जुड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब वह दिन दूर नहीं जब आप बिना इंटरनेट के भी अपना यूपीआई पेमेंट आसानी से कर सकेंगे। सामने आई एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में जल्द ही एक ऐसी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सुविधा शुरू होने जा रही है, जिसकी मदद से ग्राहक मर्चेंट के पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल पर तब भी पेमेंट कर पाएंगे, जब फोन या मशीन किसी भी डिवाइस में इंटरनेट काम न कर रहा हो।

बिना नेटवर्क वाले इलाकों में मिलेगा सबसे बड़ा फायदा

यह खास फीचर मुख्य रूप से उन जगहों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी या तो उपलब्ध नहीं होती या फिर बिल्कुल भरोसेमंद नहीं होती है। इसमें हवाई जहाज के केबिन से लेकर अंडरग्राउंड ट्रेन नेटवर्क और दूरदराज के इलाके शामिल हैं। इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को इंटरनेट कनेक्टिविटी होने पर पहले अपने डिवाइस के यूपीआई लाइट वॉलेट में पैसे लोड करने होंगे। इसके बाद जब वे ऑफलाइन होंगे, तो बिना किसी यूपीआई पिन के टर्मिनल पर टैप करके आसानी से उस बैलेंस का इस्तेमाल पेमेंट के लिए कर सकेंगे।

एनएफसी तकनीक से ऐसे पूरा होगा आपका ऑफलाइन ट्रांजेक्शन

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया साल 2026 में प्रमुख टर्मिनल बनाने वाली कंपनियों के पीओएस डिवाइस को इस नई सुविधा के लिए सर्टिफाई करना शुरू कर सकता है। इस पूरी प्रस्तावित व्यवस्था में नियर-फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत ग्राहकों को अपने एनएफसी इनेबल्ड फोन को सिर्फ ऑफलाइन टर्मिनल पर टैप करना होगा और वे बिना रुके 2,000 रुपये तक का पेमेंट चुटकियों में कर सकेंगे। जब डिवाइस ऑफलाइन होगा तब पीओएस मशीन पेमेंट ऑथराइजेशन को अपने पास स्टोर कर लेगी और जैसे ही कनेक्टिविटी वापस आएगी, उसे नेटवर्क पर आगे प्रोसेस कर देगी।

यूपीआई लाइट एक्स से कैसे अलग है यह नई व्यवस्था

आपको बता दें कि एनपीसीआई द्वारा एनएफसी का यह कोई पहला इस्तेमाल नहीं है। इससे पहले सितंबर 2023 में यूपीआई लाइट एक्स को भी पेश किया गया था, जिसे मोबाइल कनेक्टिविटी न होने पर ऑफलाइन पेमेंट के लिए डिजाइन किया गया था। यूपीआई लाइट एक्स में एनएफसी-इनेबल्ड फोन के बीच ऑफलाइन पर्सन-टू-पर्सन पेमेंट और क्यूआर कोड या साउंडबॉक्स पर टैप करके पैसे चुकाने की सुविधा दी गई थी। हालांकि, यह नया फीचर इससे एक कदम आगे है। इस नई तकनीक का सबसे बड़ा अंतर एक्सेप्टेंस हार्डवेयर का है। अब इस फीचर का विस्तार सर्टिफाइड पारंपरिक पीओएस टर्मिनलों तक किया जा रहा है, जिससे व्यापारियों को मशीन डिस्कनेक्ट होने की स्थिति में भी आसानी से पेमेंट मिल सकेगा।

आसियान की भूमिका पर QUAD की मुहर, हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए बना ये प्लान

फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला में बुधवार (22 जुलाई) को क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस दौरान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में चारों देशों ने आसियान (ASEAN) की एकता और उसकी केंद्रीय भूमिका के प्रति अपने अटूट समर्थन को दोहराया। भारत के विदेश मंत्री डॉ। एस। जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने कहा कि चारों देश आसियान के व्यापक रणनीतिक साझेदार होने के नाते क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सामने मौजूद चुनौतियों और अवसरों पर विस्तार से चर्चा हुई। विदेश मंत्रियों ने आसियान आउटलुक ऑन द इंडो-पैसिफिक (AOIP) के व्यावहारिक क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके तहत समुद्री और अंतरराष्ट्रीय अपराधों से जुड़ी सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। संयुक्त बयान में कहा गया कि हिंद-प्रशांत के समुद्री क्षेत्र में शांति और स्थिरता पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि की आधारशिला है। इसी सोच के साथ क्वाड देश क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने तथा आसियान के साथ मिलकर व्यावहारिक पहल को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अमेरिका ने लगातार 12वें दिन ईरान में बरसाए बम

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य हमले जारी हैं। अमेरिका ने लगातार 12वें दिन ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक पश्चिमी ईरान में अहवाज, रामशिर और एंडिमेस्क शहरों के पास के इलाकों पर अमेरिका ने मिसाइलों से निशाना बनाया। इस दौरान शालमचेह शहर में अमेरिकी हमले के दौरान दो लोगों की जान भी चली गई।

तेहरान पर हमले के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड का भी बयान सामने आया है। उसने कहा कि हमारे हमले का मकसद ईरान की उस क्षमता को और कम करना है जिससे वह इलाके के समुद्र से गुजरने वाले आम नाविकों और कमर्शियल जहाजों को खतरा पहुंचाता है। अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट पर फिर से नियंत्रण हासिल करने और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग को बहाल करने की कोशिश कर रहा है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार यानी 22 जुलाई को ट्रूथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ईरान को चेतावनी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था किजब भी ईरान होर्मुज स्ट्रेट में किसी जहाज पर गोलीबारी करेगा, तो अमेरिका उसके एक पुल या बिजली संयंत्र को नष्ट कर देगा।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा 'अब से, जब भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान होर्मुज स्ट्रेट में किसी जहाज पर गोलीबारी करेगा, चाहे वह मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी अन्य उपकरण या हथियार से हो तो अमेरिका एक पुल या बिजली संयंत्र पर बम गिराकर उसे नष्ट कर देगा।'

ईरान ने कहा-जैसे को तैसा नीति अपनाएगा

ट्रंप के ट्वीट के जवाब मेंईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि उनका देश 'जैसे को तैसा' वाली रक्षा नीति अपनाएगा। उन्होंने बुधवार को X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईरान के खिलाफ कोई भी आक्रामकता, जिसमें हमारे बुनियादी ढांचे पर हमला भी शामिल है, एक शक्तिशाली और निर्णायक प्रतिक्रिया को मजबूर करेगी।

बुनियादी ढांचे पर हमले होने शुरू हुए

ईरान और अमेरिका ने अब एक-दूसरे के खिलाफ नागरिक और बुनियादी ढांचे पर हमला करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ईरान में बिजली संयंत्रों, पुलों और डिसेलिनेशन प्लांटों को निशाना बनाया। वहीं, ईरान में भी कुवैत और कतर के डिसेलिनेशन प्लांट यानी खारे पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्रों पर पर हमले किए।

पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ रही हैं

होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के चलते विश्व अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। इसके अलावा यमन में ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों की ओर से रेड सी में सऊदी जहाजों को निशाना बनाने की नई धमकी से व्यापार का एक और अहम रास्ता खतरे में पड़ गया है। इन सबके बीच ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 93 डॉलर प्रति बैरल से ज़्यादा हो गई है।यह इस महीने की शुरुआत में 72 डॉलर प्रति बैरल से कम थी, जो युद्ध से पहले की कीमत के लगभग बराबर थी। पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं।

युद्ध में अब तक 37।5 अरब डॉलर खर्च

युद्धा से अमेरिका को भी भारी नुकसान हो रहा है। 22 जुलाई को डोवर एयर फोर्स बेस पर अमेरिकी सेना के 4 जवानों के शव लाए गए थे। एक दिन पहले, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सीनेट की एक सुनवाई में अनुमान लगाया था कि, ईरान के साथ युद्ध में देश के 37।5 अरब डॉलर खर्च कर दिए गए हैं।

इबोला के कहर से कांगो त्रस्त, वायरस के नए वैरिएंट ने मचाई तबाही, 2 महीने में ही 1 हजार से अधिक की मौत

कांगो। अफ्रीका में इबोला वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। एक छोटे से देश कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक एक हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अफ्रीका की प्रमुख स्वास्थ्य संस्था के अनुसार, कांगो में इबोला का कहर जारी है। यह इतिहास का सबसे तेजी से फैलने वाला इबोला प्रकोप है, जिसमें संघर्ष, समुदाय का विरोध और असमान प्रतिक्रिया इस वायरस को तेजी में फैला रहे हैं।

घाना में बुधवार को आयोजित एक स्वास्थ्य सम्मेलन में बोलते हुए, अफ्रीका सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के महानिदेशक डॉ। जीन कासेया ने कहा कि कांगो में 1,031 मौतों की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा, "लोग तेजी से मर रहे हैं। वे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं हैं, दवाइयां नहीं हैं और फंड भी नहीं है।"

कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, सोमवार तक इस वायरस के 2,473 नए केस दर्ज किए गए थे। मंत्रालय ने बताया कि कम से कम 737 मरीज आइसोलेशन में थे या अस्पताल में भर्ती थे। 15 मई को घोषित यह वैरिएंट पिछले कई इबोला वायरस से थोड़ा अलग है क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार बुन्डिबुग्यो वैरिएंट के लिए कोई स्वीकृत वैक्सीन या दवाई सामने नहीं आ सकी है।

इसने रिकॉर्ड पर मौजूद किसी भी अन्य वायरस की तुलना में इसने तेजी से और अधिक लोगों की जान ली है, इसमें 2013-2016 का प्रकोप भी शामिल है, जिसे अब तक का सबसे बुरा प्रकोप माना जाता है। इस केस में कम से कम 28,000 केस सामने आए और उसमें से 11 हजार से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। तब उस वायरस से जुड़े पहले केस से लेकर 1 हजार मौतों तक पहुंचने में करीब 8 महीने लगे थे।

पीड़ितों के असल आंकड़े इससे अधिक

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि वायरस के कहर का सही आंकड़ा इससे कहीं बड़ा हो सकता है और आधिकारिक आंकड़ों की तुलना में 2 से 4 गुना बड़ा हो सकता है। क्योंकि इन इलाकों में कुछ ऐसे समुदाय भी हैं जहां तक पहुंच पाना संभव नहीं होता और इसकी वजह विद्रोही गुटों के बीच चल रही लड़ाई है। इबोला एक दुर्लभ लेकिन अत्यधिक संक्रामक बीमारी है और यह वायरस उल्टी, खून या वीर्य जैसे शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैल सकती है। इसकी वजह से गंभीर बीमारी हो सकती है और कई बार यह जानलेवा साबित होती है।

अधिकारियों ने आगाह किया है कि वायरस से जुड़े 80% नए केस संक्रमण की ज्ञात जगहों से बाहर के हैं, जो यह बताता है कि वायरस स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा ट्रैक किए जा सकने की गति से भी तेजी से फैल रहा है। जबकि ये स्वास्थ्य अधिकारी वायरस के केंद्र इतुरी प्रांत और चार अन्य प्रांतों, जहां मामले दर्ज किए गए हैं, में अपनी प्रतिक्रिया तेज कर रहे हैं।

शव दफनाने भी बनी बड़ी चुनौती

इबोला वायरस से मरने वालों के शव को दफनाना भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। सुरक्षित तरीके से शव दफनाने वाली टीमों का कई समुदायों की ओर से विरोध किया जा रहा है, जिससे समस्या बढ़ गई है। इतुरी प्रांत में कुछ समुदायों ने दफनाने वाली टीमों को काम करने से मना कर दिया है, क्योंकि वे पारंपरिक तरीके से शव दफनाते हैं, लेकिन इससे बीमारी के और फैलने का खतरा बढ़ जाता है। शव दफनाने वाली पर हमले किए जा रहे हैं। इस वजह से कई स्वास्थ्य केंद्रों और बचाव टीमों पर हमलों की वजह से फ्रंट-लाइन पर काम करने वाले लोग और सहायता समूह कुछ इलाकों से हट गए हैं। कुछ स्वास्थ्यकर्मियों ने हड़ताल कर दी है, उनका कहना है कि बीमारी फैलने के बाद से उन्हें वेतन नहीं मिला है।

सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की छूट! 2008 की भारत-US न्यूक्लियर डील से कितना अलग है यह समझौता?

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी मीडिया की खबरों के मुताबिक, यूएस और सऊदी अरब एक समझौते का ऐलान करने वाले हैं। इस समझौते के तहत सउदी अरब को अपना सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम विकसित करने की मंजूरी मिल जाएगी। इसके जरिए सऊदी अरब अपनी जमीन पर यूरेनियम का एनरिचमेंट कर सकेगा। अमेरिकी कंपनियों को एनरिच्ड यूरेनियम विकसत करने वाले प्लांट को बनाने का काम मिल सकता है।

यह समझौता अमेरिका के उस समझौते से अलग होगा, जो उसने 2009 में सऊदी अरब के पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ किया था। उस समझौते के तहत UAE अपना ईंधन खुद नहीं बनाता है। इसके अलावा कई अन्य प्रतिबंधों को भी मानता है।

अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने जा रहे हैं इस संभावित समझौते पर परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने (नॉन-प्रोलिफरेशन) की वकालत करने वालों की चिंता भी बढ़ सकती है, जिनका मुख्य मकसद दुनिया भर में परमाणु हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी को रोकना है।

उधर ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल के बीच महीनों से चल रहे टकराव का केंद्र भी परमाणु मुद्दा ही रहा। दोनों देशों का कहना था कि ईरान पर हमला करने की एक वजह यह थी कि उसे परमाणु हथियार विकसित करने से रोका जा सके। ऐसे में अमेरिका करीबी सहयोगी इजराइल के परमाणु विशेषज्ञों और पूर्व अधिकारियों ने चिंता जताई है कि इस योजना के कारण सऊदी अरब भविष्य में परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता हासिल कर सकता है।

हालांकि,सऊदी अरब के वास्तविक शासक, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि उनका देश परमाणु हथियार हासिल करने की योजना नहीं बना रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर ईरान परमाणु बम बनाता है, तो हम भी जल्द से जल्द वैसा ही करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, बुधवार को सामने आने वाले अमेरिका-सऊदी समझौते को ट्रंप पहले ही मंज़ूरी दे चुके हैं और यह समझौता 30 साल तक लागू रहेगा। परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाला ईंधन प्राकृतिक यूरेनियम से तैयार किया जाता है। इसमें मौजूद U-235 आइसोटोप की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया को यूरेनियम संवर्धन कहते हैं।

टूटी हड्डी पर बैंड-एड लगाने जैसा...

पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के ऐलान पर बोली सीजेपी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेपर लीक मामले पर फास्ट ट्रैक कोर्ट से जांच कराने के ऐलान पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने कहा कि यह टूटी हड्डी पर बैंड-एड लगाने जैसा है। पीएम का ट्वीट छात्रों के साथ एक क्रूर मजाक है। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर PM मोदी से सवाल किया कि वे आखिर छात्रों और युवाओं की जगह धर्मेंद्र प्रधान (शिक्षा मंत्री) को प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं?

सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने पीएम नरेंद्र मोदी की बात का जवाब देते हुए बयान जारी कर कहा, "पेपर लीक मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट की घोषणा कोई असली समाधान नहीं है। यह सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री देशभर के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ क्रूर मजाक कर रहे हैं।" कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा,

"पेपर लीक इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि देश में फास्ट-ट्रैक कोर्ट की कमी है। ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरह से अक्षम साबित हुए हैं। लेकिन वे एक सुरक्षित और फूलप्रूफ परीक्षा प्रणाली बनाने में नाकाम रहे हैं। आज, देश के युवा सबसे ज्यादा एक ही चीज की मांग कर रहे हैं और वो है जवाबदेही।"

आशुतोष रंका ने आगे कहा, "पीएम मोदी का प्रस्तावित समाधान टूटी हुई हड्डी पर बैंड-एड लगाने जैसा है। पेपर लीक की समस्या बहुत गहरी है। हमारी परीक्षा प्रणाली अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी है। जब तक सिस्टम की कमियों को दूर नहीं किया जाता, पेपर लीक होते रहेंगे।"

पार्टी ने आगे कहा, "छात्रों को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं के वादों की जरूरत कोई नहीं है। वे तुरंत न्याय और जवाबदेही के हकदार हैं। यह जवाबदेही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई से शुरू होनी चाहिए।"

4 मांगें माने जाने तक जारी रहेगा प्रदर्शन : सीजेपी

कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अंत में कहा, "CJP तब तक अपना विरोध जारी रखेगा जब तक सरकार उसकी इन 4 मांगों को मान नहीं लेती। पहला, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरा, खुदकुशी करने वाले बच्चों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। तीसरा, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर किसी तरह का कोई केस नहीं चलाया जाएगा। चौथा, ज्यादती करने वाले सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस चलाया जाए।" पीएम मोदी के ऐलान पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री के पोस्ट को कोट करते धर्मेंद्र प्रधान की एक तस्वीर के साथ लिखा, "Hi, my name is nothing"। यह PM मोदी और प्रधान दोनों पर निशाना साधते हुए किया गया था, क्योंकि सरकार अड़ी हुई है और शिक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं मांग रही है।

सोनम रघुवंशी की जमानत सुप्रीम कोर्ट से रद्द, हनीमून के दौरान पति की हत्या का है आरोप

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजा मर्डर केस में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द की और उसे तीन हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया। सोनम पर मेघालय में हनीमून के दौरान पति की हत्या का आरोप है। शीर्ष अदालतने कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी। प्रतिवादी को गिरफ्तारी की वजह बताई गई थी। हत्या के बाद प्रतिवादी यानी सोनम गायब थीं, जिसका कोई वजह उनके पास नहीं है। ऐसे में वह मेरिट के आधार पर जमानत की हकदार नहीं हैं। सोनम तीन हफ्ते में सरेंडर करें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल में देरी होती है तो सोनम छह महीने बाद फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकती हैं। शीर्ष अदालत ने आगे ये भी कहा कि हम इस बात से भी वाकिफ हैं कि जमानत मिलना नियम है और जेल अपवाद है। हालांकि, हम ऐसे मामले पर विचार कर रहे हैं, जिसमें जमानत की अर्जी को मेरिट के

आधार पर पहले ही खारिज किया जा चुका है और वे आदेश अंतिम हो चुके हैं।

कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि इस चरण पर जमानत जारी रखने से चल रही सुनवाई में बाधा आ सकती है। हम विवादित आदेश को रद्द कर रहे हैं। प्रतिवादी को सरेंडर करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया जाता है। अगर मुकदमे की सुनवाई 6 महीने के भीतर आगे नहीं बढ़ती या पूरी नहीं होती है, तो प्रतिवादी नई जमानत अर्जी दाखिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट मेघालय सरकार की उस याचिका पर आदेश जारी किया, जिसमें हाई कोर्ट से सोनम को मिली जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी।

शीर्ष अदालत ने और क्या कहा?

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने आदेश में दर्ज किया कि अपील को इजाजत दी गई। अपील करने वाली पार्टी ही प्रॉसिक्यूशन एजेंसी है। वह रेस्पॉन्डेंट (प्रतिवादी) को जमानत मिलने से नाराज है। अपील करने वाले का मुख्य तर्क यह है कि शादी के बाद वह मृतक के साथ मेघालय गई थी। हनीमून के दौरान मृतक की हत्या कर दी गई और फिर अपील करने वाले और सह-आरोपी द्वारा किराए पर लिए गए तीन साथियों की मदद से उसे एक खाई में धकेल दिया गया। इसके बाद उसका कोई पता नहीं चल सका। जब उसके ठिकाने का पता नहीं चला, तो FIR दर्ज की गई। 9 जून 2026 को गिरफ्तारी की गई।

कोर्ट ने कहा कि रेस्पॉन्डेंट ने मेरिट के आधार पर रिहाई के लिए एक के बाद एक कई ज़मानत अर्जियां दाखिल कीं। उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, रिहाई के लिए एक और अर्जी दाखिल की गई, जो इस अपील का मुख्य विषय है। इसमें हिरासत के आधारों की जानकारी न देने के नियम का पालन न करने का मुद्दा उठाया गया। रेस्पॉन्डेंट का यह भी कहना है कि हिरासत के तथाकथित आधारों को सही मायने में आधार नहीं माना जा सकता क्योंकि उनमें जरूरी जानकारी का अभाव है। उनकी दलीलों को मानते हुए उन्हें जमानत दे दी गई।

'हर आवाज को सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए' : छात्र आंदोलन पर बोले राजकुमार राव, शांति को बताया सबसे बड़ी ताकत

नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन पर अभिनेता राजकुमार राव ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर लिखा है कि हर आवाज को पूरे सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए।

नीट पेपर लीक के बाद सोशल मीडिया पर शुरू हुई मुहिम अब सड़क पर आंदोलन के रूप में देखी जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सितारे भी छात्रों के साथ आए हैं और उनके लिए आवाज बुलंद की है। कुछ प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं तो कुछ सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा रहे हैं। एक्टर राजकुमार राव ने भी एक पोस्ट शेयर किया है।

बोले- 'यह बातचीत और संवेदना का समय है'

राजकुमार राव ने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, 'जब युवाओं को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो यह याद दिलाता है कि समाज को उनकी बात सुननी चाहिए। हर आवाज को सम्मान, निष्पक्षता और आदर के साथ सुना जाना चाहिए। साथ ही, शांति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। किसी भी तरफ से होने वाली हिंसा केवल घावों को गहरा करती है और हमें सार्थक समाधानों से दूर ले जाती है। यह बातचीत और संवेदना का समय है'।

'देश के विकास का आधार निष्पक्ष शिक्षा'

एक्टर ने आगे लिखा है, 'विद्यार्थियों को स्वयं को जिम्मेदारीपूर्वक अभिव्यक्त करने दें। अधिकारियों को सहानुभूति, खुलेपन और सुनने की सच्ची इच्छा के साथ जवाब देने दें। वास्तविक और स्थायी परिवर्तन बातचीत से आता है, टकराव से नहीं। इसी की अब आवश्यकता है। पहले से कहीं अधिक। हम सभी मिलकर एक चीज चाहते हैं, अपने देश का विकास और उस विकास का आधार है निष्पक्ष शिक्षा। जय हिन्द'। राजकुमार राव ने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा है, 'यह ठीक से नहीं जम पाया। प्लीज किसी दूसरे प्रॉम्प्ट के साथ फिर से कोशिश करें'।

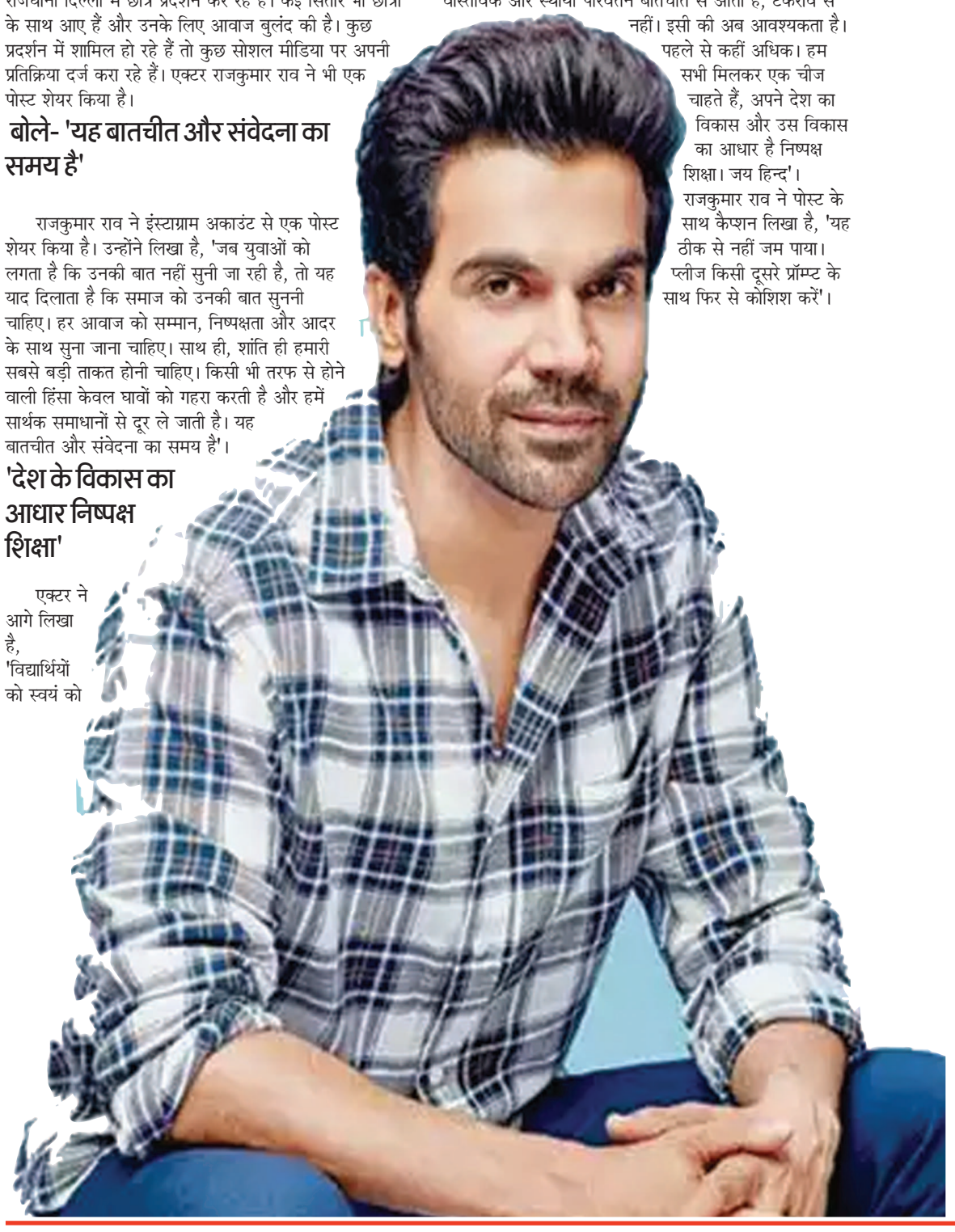

'मैं ठीक हूं...; पोस्ट को गलत समझा गया'; नहीं हुई अमिताभ बच्चन की सर्जरी, ICU वाले ब्लॉग पर बिग बी ने दी सफाई

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन नियमित ब्लॉग लिखते हैं। मगर, बीते दिन उन्होंने कुछ ऐसा लिखा, जिसके बाद फैंस को उनके स्वास्थ्य की चिंता होने लगी। बिग बी ने अपने पोस्ट में सर्जरी और आईसीयू का जिक्र किया। उनके इस पोस्ट के आधार पर लोगों ने यह कयास लगाए कि शायद उनकी सर्जरी हुई है। मगर, ऐसा नहीं है। एक और पोस्ट साझा कर अमिताभ बच्चन ने सफाई दी है।

ब्लॉग में लिखा- 'मैं ठीक हूं...'

अमिताभ बच्चन ने हालिया ब्लॉग पोस्ट में यह साफ किया है कि वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनकी सर्जरी नहीं हुई है, उनके पोस्ट को लेकर गलतफहमी हुई है। अभिनेता ने कहा कि उनका पोस्ट फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना की हार को लेकर था। अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग में लिखा है, 'मैं ठीक हूं...; पोस्ट को गलत समझा गया। मैं बस एक उदाहरण दे रहा था। सर्जरी या ICU में रहने के बाद, सबसे मुश्किल समय तब होता है जब आप घर लौटते हैं और अपनी कमजोर हालत का सामना करते हैं। तो.. जब कोई चैंपियन हारता है, तो हार के बाद खुद को संभालना सबसे मुश्किल काम होता है'।

बोले- 'जिंदगी ऐसी ही है'

अमिताभ बच्चन ने आगे उदाहरण के साथ अपनी बात समझाते हुए लिखा है, 'उदाहरण के लिए..., अर्जेंटीना की हार और मेसी का हारने वाला चैंपियन बनना। लोगों को लगा कि यह मेरे बारे में है। गलतफहमी थी। हर चैंपियन को यह पता होना चाहिए कि समय के साथ कोई और

चैंपियन भी आएगा। किसी चैंपियन के लिए यह मानना मुश्किल होता है कि किसी और ने उसकी जगह ले ली है, लेकिन जिंदगी ऐसी ही है, यह हमेशा चलता रहेगा'।

'चैंपियन अपनी हार से उबर सकता है'

अमिताभ बच्चन ने आगे लिखा है, 'मान लीजिए आप अस्पताल जाते हैं (भगवान न करे ऐसा हो) किसी ऐसी बीमारी के इलाज के लिए, जिसमें ठीक होने की जरूरत हो। जब आप गए थे तो आपका शरीर ठीक था, लेकिन सर्जरी या इलाज के बाद बीमारी तो ठीक हो जाती है, पर उसके बाद शरीर को संभालना मुश्किल होता है। हो सकता है कि शरीर पहले जैसा काम न करे और उस बदलाव को स्वीकार करना मुश्किल होता है। शरीर कमाल का होता है, यह खुद को ढाल लेता है, काम करता है, लेकिन शायद पहले जैसा नहीं। हारने वाले चैंपियन को भी ऐसी ही भावनाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन, वे डटकर मुकाबला करते हैं। जब शरीर पर मेहनत की जाती है तो नतीजे मिलते हैं, शायद पहले जैसे न हों, लेकिन नतीजे जरूर मिलते हैं। चैंपियन अपनी हार से उबर सकता है और फिर से चैंपियन बनने के लिए लड़ सकता है।

गेम ऑन, स्टाइल ऑन! लॉर्ड्स में भारत–इंग्लैंड मैच के दौरान जाह्नवी कपूर का पावरफुल फैशन स्टेटमेंट

जाह्नवी कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह हर मौके पर अपने फैशन सेंस से लोगों का दिल जीतना बखूबी जानती हैं। अभिनेत्री हाल ही में लंदन के प्रतिष्ठित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच का आनंद लेने पहुंचीं, जहां उनका स्टाइलिश अंदाज देखते ही बन रहा था।

इस खास मौके पर जाह्नवी ने राल्फ लॉरेन का टेलर्ड ब्लेज़र और मैचिंग ट्राउज़र पहनकर क्लासिक एलिगेंस और मॉडर्न पावर ड्रेसिंग का शानदार मेल पेश किया। उन्होंने अपने लुक को मिनिमल एक्सेसरीज़, सॉफ्ट ग्लैम मेकअप और सिग्नेचर स्लीक हेयरस्टाइल के साथ पूरा किया, जिससे उनके आउटफिट का शार्प सिल्हूट और भी उभरकर सामने आया।

जहां क्रिकेट प्रेमियों की नजरें मैदान पर चल

रहे रोमांचक मुकाबले पर टिकी थीं, वहीं स्टैंड्स में मौजूद जाह्नवी कपूर ने अपने बेहतरीन फैशन चॉइस से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनका यह शानदार लुक लॉर्ड्स के शाही और ऐतिहासिक माहौल के साथ पूरी तरह मेल खा रहा था, जिसे होम ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है।

रेड कार्पेट हो या फिर क्रिकेट स्टेडियम, जाह्नवी कपूर हर बार अपने स्टाइल से एक नया फैशन गोल सेट करती हैं। भारत-इंग्लैंड मैच के दौरान उनका यह एलिगेंट और पावरफुल लुक एक बार फिर साबित करता है कि किसी भी मौके पर फैशन के खेल में जीतना उन्हें बखूबी आता है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com